मर्द, मर्दनिगी और महामारी

उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के साथ प्रोग्रामिंग पर कोविड-19 का प्रभाव

मर्द, मर्दानगी और महामारी

उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के साथ प्रोग्रामिंग पर कोविड-19 का प्रभाव

विषय-सूची

परिचय	02
रैशनेल	04
अध्ययन का डिज़ाइन	06
क्रियाविधि	06
सीमाएं	07
इंटरव्यू लिए जाने वाले संस्थाओं की बैकग्राउंड	08
निष्कर्ष और विश्लेषण	09
उभरती ज़रूरतें और बढ़ते संपर्क	09
“क्या आप मुझे सुन सकते हैं?” : “नए नार्मल” को अपनाना	11
प्रोग्रामिंग बैकसीट पर	12
विषय आधारित सहभागिताओं पर प्रभाव	13
I. लाइवलीहुड	13
II. शिक्षा	14
III. स्वास्थ्य	15
V. हिंसा और मर्दानगी	17
हमने क्या सर्वोत्तम किया...	22
i) हितधारकों को जोड़ना	22
ii) मिली-जुली चर्चाओं के आयोजन	22
कोविड का एक वर्ष: आगे क्या करना है?	23
(i) विषय आधारित विस्तार	24
(ii) ऑनलाइन या ऑफलाइन?	24
(iii) फंडिंग की समस्याएं	
निष्कर्ष	26
मिली-जुली प्रोग्रामिंग की दिशा में	26
बेहतर पुनर्विकास (बिल्डिंग बैक बेटर)	29
संदर्भ	30
परिशिष्ट	33

अभिस्वीकृतियां

यह अध्ययन परियोजना, उत्तर प्रदेश में विभिन्न अलाभकारी संस्थाओं से जुड़े, विकास क्षेत्र के सभी पेशेवरों की सहभागिता के बिना संभव नहीं थी, जिन्होंने अपने अमूल्य अनुभवों और ज्ञान से इस कार्य को समृद्ध बनाया और हमें विभिन्न संस्थाओं और नेटवर्कों से जोड़ा। हम अपने सभी उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए समय, उनके प्रयास और उत्साह के लिए उनके हार्दिक आभारी हैं जिन्होंने अनेक इंटरव्यू और वार्तालापों के माध्यम से, लॉकडाउन और कोविड-19 संकट की पहली लहर के बारे में अपनी कहानियों से इस परियोजना में योगदान दिया। यह रिपोर्ट, विभिन्न विषयों में युवा पुरुषों और लड़कों से संबंधित विकास कार्य पर कोविड-19 के प्रभाव समझने के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए उनको समर्पित है।

हम अपने सलाहकार सदस्यों के अंतहीन सहयोग और धैर्य के लिए उनके भी आभारी हैं: क्रिस्टीना फ़र्टाडो (एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन) और विकास चौधरी (मूल्यांकन, अध्ययन और अधिगम सलाहकार, आईपीपीएफ -एसएआरओ)। परियोजना के अवधारणा स्तर, अध्ययन उपकरणों का निर्धारण तथा विश्लेषण और रिपोर्ट प्रारूपों की समीक्षा सहित अध्ययन प्रक्रिया के हर चरण में उनके इनपुट और सुझाव, हमारे लिए यह कार्य पूरा करने में अत्यंत सहायक रहे हैं। यह अध्ययन उनके मार्गदर्शन और दिशानिर्देश के बिना इस रूप में आकार नहीं ले सकता था।

हम सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआरआई) के संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आईआरबी) के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस अध्ययन के टूल्स की एक नैतिक समीक्षा की, निहारिका सिंह और चैताली पंत जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन कार्य किया, और डॉ. संजय जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश में काम करने वाली कई संस्थाओं से जोड़ा।

इस परियोजना में सहयोग देने के लिए अमेरिकन ज्यूइश इंस्टीट्यूट और खासतौर से हमारे कार्य में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए मंजिमा भट्टाचार्य के भी आभारी हैं।

परिचय

भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के एक वर्ष बाद भी, विविध क्षेत्रों के अध्ययनकर्ताओं, प्रोग्राम लागू करने वालों और हितधारकों द्वारा मोटे तौर पर समाज पर तथा विभिन्न समुदायों पर आजीविका, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा और जेंडर न्याय के विशेष मुद्दों पर इस संकट के प्रभाव को समझने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड-19 संकट की पहली लहर पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए 22 मार्च 2020 को भारत की केंद्र सरकार ने एक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, जो 18 मई 2020 तक लगा रहा। इस समय के दौरान केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे कि राशन, भोजन, दवाओं और अन्य स्वास्थ्यसेवा संबंधी चीज़ों की उत्पादन की अनुमति दी गई, जबकि अन्य आर्थिक गतिविधियां जैसे की गैर-अनिवार्य चीज़ों और सेवाओं का उत्पादन और व्यापार बंद रहा।

देश में विविध आर्थिक गतिविधियों को इस तरह अचानक बंद कर दिए जाने के कारण, अनेक युवा लोगों की नौकरियां और आजीविकाओं पर ख़ासतौर से विनाशकारी प्रभाव पड़ा। महामारी के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आमदनी के नुकसान और खाद्य असुरक्षा की स्थितियां उत्पन्न हुईं। इससे, देश भर में कम आमदनी वाले परिवारों को अपने भोजन और राशन की ज़रूरतों में कटौती करनी पड़ी, अपने जीवन भर की बचत ख़र्च करनी पड़ी और उनके पोषक तत्वों के सेवन में कमी आई।[1] कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के अधिकांश नकारात्मक प्रभाव, अनौपचारिक क्षेत्र में तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों में देखे गए।[2] शहरों में किराया दे पाने या राशन जुटा पाने में अक्षमता के कारण गाँवों और गृह-शहरों की तरफ बड़े पैमाने पर लोगों का वापस पलायन हुआ।[3] इसके अलावा, आर्थिक गतिविधि सुधारने के इरादे से उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने एक अध्यादेश पारित करते हुए श्रम कानूनों जैसे कि कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम में छूट प्रस्तावित कीं। इससे बिजनेसों को अनेक प्रमुख श्रम अधिकारों और मौजूदा नीतिया, जैसे कि कानूनी अनुमत कार्यशील घंटों की सीमा को बढ़ाया गया और इससे भी वर्करों के लिए अनिश्चितता और अधिक बढ़ गई।[4]

शिक्षा के क्षेत्र में, संकट पर प्रतिक्रिया के रूप में अनेक स्कूल 16 मार्च 2020 से बंद हो गए। इस व्यवधान ने ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले लगभग 84% छात्रों और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 70% छात्रों को प्रभावित किया।[5] इससे, भोजन और पोषण से जुडी सरकारी योजनाओं जैसे कि मध्यान्ह भोजन योजना पर निर्भर छात्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही, छात्रों को जोड़े रखने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट के उपयोग पर दिए गए जोर से, ग्रामीण भारत के लोगों के बीच पहले से मौजूद डिजिटल अंतराल और अधिक बढ़ गया जिससे स्थानीय स्कूलों से सीमांत छात्रों के ड्रॉपआउट दरों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई।[6] अधिकांश मामलों में, लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, जिससे युवा महिलाओं और लड़कियों का ड्रॉपआउट ज़्यादा बड़ा।[7]

1 इनानी आर. (2021, जनवरी 22)। इंडियाज पुअर आर ईटिंग इनटू देयर सेविंग्स, थैंक्स टु हाई इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 इंडियास्पेंड: डेटा जर्नलिज्म, एनालिसिस ऑन इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थकेयर,एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स । https://www.indiaspend.com/economy/indias-poor-are-eating-into-their-savings-thanks-to-high-inflation-covid-19-716956
2 मंदर, एच. (2021)। लॉकिंग डाउन दि पूअर (2021 ed.)। स्पीकिंग टाइगर बुक्स।
3 चौरसिया, एम. , एवं पीटरसन, एच. ई. (2020, जुलाई 1)। इंडियारैक्ड बाय दि ग्रेटेस्ट एक्सडस सिंस पार्टिशन ड्यू टू कोरोनावायरस । दि गार्जियन। https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/india-wracked-by-greatest-exodus-since-partition-due-to-coronavirus
4 इन्फार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश (2020) '6/7 press note.pdf-Google Drive' अवैलेबल एट: https://drive.google.com/file/d/1cwpaqzYaWBt_I_7U2rusRJ0qZZ8yQiDe/view
5 रवि आर. सी. (2020) लॉकडाउन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ड्यू टू कोविड-19: एनी इंपैक्ट ऑन दि एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया? जर्नलिज्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोमोशन, 9, 209। https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_327_20
6 पांडे, के. (2020, जुलाई 30)। कोविड-19 लॉकडाउन हाइलाइट्स इंडियाज ग्रेट डिजिटल डिवाइड। डाउन टू अर्थ। https://www.downtoearth.org.in/news/governance/covid-19-lockdown-highlights-india-s-great-digital-divide-72514
7 सोनवाने, एस. (2020, दिसम्बर 1)। दि जेंडर्ड इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्कूल एजुकेशन। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी। https://www.cbgaindia.org/blog/gendered-impact-covid-19-school-education/

स्वास्थ्य क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव खासतौर से खराब था। संकट की पहली लहर के दौरान भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सेक्टर ने अस्पतालों, डॉक्टरों, पीपीई किटों, टेस्टिंग किटों और अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी का सामना किया। इसके अलावा, विभिन्न केंद्र सरकार [8] द्वारा स्वास्थ्य पर ऐतिहासिक रूप से किए गए कम खर्च के कारण लोगों के लिए स्वास्थ्यसेवाओं पर आकस्मिक खर्च पहले ही काफी बढ़ा हुआ था इस स्थिति में सीमांत समुदायों और ऊपरी मध्यम परिवारों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों और उपलब्धता का अंतराल और भी ज़्यादा बढ़ गया।

जहां सरकारें, महामारी के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से जूझ रही थीं, वहीं यौन और जेंडर-आधारित हिंसा (एसजीबीवी) के मामलों की तादाद में बढ़ोत्तरी के साथ इसके लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया करने वाली व्यवस्थाएं, लॉकडाउन के दौरान चरमरा गई थीं। [9] हिंसा में बढ़ोत्तरी न केवल ऑफलाइन रूप से परिवारों और घरों में हुई थी, बल्कि ऑनलाइन मामले में भी, जहां साइबर हिंसा जैसे कि डॉक्सिंग (दूसरों की पहचान उजागर करना)[10], यौन चित्र जारी करना या छेड़छाड़ किए हुए चित्र साझा करना आदि की घटनाओं की भी रिपोर्ट की गई थी।[11] लॉकडाउन के कारण एसजीबीवी के विविध रूपों में इस कुल बढ़ोत्तरी को यूएन वीमेन ने "शैडो महामारी" का नाम दिया। अन्य तरह की हिंसा के मामले, जिनमें जाति- आधारित हिंसा [12,13] और पुलिस की क्रूरता भी शामिल है ,[14] के बारे में भी भारतीय मीडिया द्वारा सूचित किया गया।

इस व्यापक संदर्भ में उत्तर प्रदेश के युवा पुरुषों और लड़कों को शामिल करने वाले विकास प्रोग्राम को कोविड-19 संकट की पहली लहर के दौरान समझे गया है। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद आयोजित सर्वेक्षण आधारित अध्ययन अध्ययनों ने देश भर में विकास प्रोग्रामों पर कोविड-19 संकट के प्रभाव को दर्ज किया [15]। संस्थाओं ने बताया, कि कोविड-19 का प्रभाव कई स्तरों पर अनुभव किया गया है। पहली बात, महामारी का सामना करना और इस पर प्रतिक्रिया करना, दुनिया भर की सरकारों के लिए एक प्राथमिकता । संस्थाओं ने बताया, कि कोविड-19 का प्रभाव कई स्तरों पर अनुभव किया गया है। पहली बात, महामारी का सामना करना और इस पर प्रतिक्रिया करना, दुनिया भर की सरकारों के लिए एक प्राथमिकता जरूरत बन गई, वित्तपोषण और दानदाता संस्थाओ ने अपने फंड कोविड-19 से संबंधित राहत कार्यों के लिए निर्धारित किए ताकि कोविड-19 संकट के लिए गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया को मज़बूत बनाया जा सके। इससे उन विकास कार्यों के वित्तपोषण की तात्कालिक प्राथमिकता कम हो गई जो इस संकट से संबंधित नहीं थे, इसका असर विकास कार्य करने वाली उन संस्थाओं पर पड़ा, जिनके कार्य इस संकट पर प्रतिक्रिया या महामारी या स्वास्थ्य से संबंधित नहीं थे। यह प्रभाव, भारत में स्थानीय संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से संबंधित नीतिगत बदलावों की वजह से और भी गहरा हो गया। दूसरी बात, भारत सरकार द्वारा किए गए नीतिगत फैसले और प्रतिक्रिया के उपाय, जैसे कि देशव्यापी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, आवाजाही पर प्रतिबंध, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद किया जाना और वर्क फ्रॉम होम आदि उपायों ने उनके प्रोग्रामों को प्रभावित किया, जिनकी विषयवस्तु और प्राथमिकताओं, सहभागिता के मॉडलों, प्रोग्राम डिलीवरी की रणनीतियों और प्लेटफार्मों, परियोजना की समयसीमाओं, लामबंदी और पहुंच वाली गतिविधियों और निगरानी और मूल्यांकन क्षमताओं आदि के संदर्भ में अनिवार्य रूप से बदलाव हो गए।[16]

8 पीटीआई। (2020, नवम्बर 19)। इंडियाज ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन दि हेल्थ सेक्टर लो, सेज नीति आयोग मेम्बर। दि हिंदू। https://www.thehindu.com/news/national/indias-overall-spending-on-health-sector-low-says-niti-aayog-member/article33132569.ece

9 यूएन वीमेन। (2020)। कोविड-19 एंड एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

10 किसी को परेशान करने के इरादे से, उसकी सहमति के बिना, उसकी निजी जानकारी जैसे कि पता, फोन नंबर, कार्यस्थल आदि की जानकारी प्रकाशित करना डॉक्सिंग कहलाता है।

11 एक्सप्रेस न्यूज सर्विस। (2021, जनवरी 7)। ऑफ्टर कोविड, केसेज ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट स्पाइक्ड बाय 5 टाइम्स। दि इंडियन एक्सप्रेस। https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/after-covid-cases-of-online-harassment-spiked-by-5-times-7137386/

12 टीएन: एट लीस्ट 30 मेज़र इंसिडेंट्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, सेज स्टडी। (2020, सितम्बर 18)। न्यूजक्लिक। https://www.newsclick.in/Tamil-Nadu-Caste-Based-Violence-COVID-19-Lockdown

13 मिंट। (2020, अगस्त 21)। मिलियंस एस्केप्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोविड-19 ब्रॉट इट बैक। https://www.livemint.com/news/india/millions-escaped-caste-discrimination-covid-19-brought-it-back-11597974483827.html

14 कलिता के.के. (2020, जुलाई 16)। पुलिस ब्रूटैलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन एंड इंडियन मेजॉरिटी क्लासेज। नार्थईस्ट नाउ। https://nenow.in/opinion/police-brutality-against-vulnerable-and-indian-majority-classes.html

15 डेलोइट। (2020, अक्टूबर)। सोशल रिस्पांस टू कोविड-19: रोडमैप टू रिकवरी थ्रू डेवेलपमेंट एंड सीएसआर इनीशिएटिव्स। https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-about-deloitte-covid-19-response-document-indias-development-sector-noexp.pdf

16 डेवेलपमेंट सेक्टर : एडॉप्टिंग टू दि न्यू इकोसिस्टम इन दि कोविड-19 एरा। (2021, मार्च)। वी कम्युनिकेशन। https://we-worldwide-arhxo0vh6d1oh9i0c.stackpathdns.com/media/450023/avian-we-social-impact-whitepaper_digital_03152021.pdf

रैशनेल

टीवाईपीएफ के कार्यों पर कोविड-19 का प्रभाव, देश भर में विकास संस्थाओं पर देखा गया है। कोविड-19 के कारण हमारे कार्य और परिचालनों तथा जिन समुदायों के साथ हम कार्य करते हैं, पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। शुरुआती लॉकडाउन के कारण सभी प्रोग्रामों को क्षेत्र पर लागू करने का काम रुक गया और अक्टूबर 2020 तक 7 महीनों तक रुका रहा। सितम्बर तक हम ऑनलाइन सहभागिता विधियों के माध्यम से कुछ ऐसे समुदायों से सहभागिता बहाल कर सके जिनकी इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुँच थी। दिल्ली में प्रवासीप्रवासी समुदायों के बीच कार्यक्रम बंद हो गए क्योंकि ज़्यादातर परिवारों को, जिनमें किशोर भी थे, दिल्ली से अपने शहर जाना पड़ गया। मई 2021 से, हम ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करके ट्रेनरों की ट्रेनिंग जारी रखने में सक्षम हो सके। हमारे कुछ पाठ्यक्रम आधारित प्रोग्रामों के क्षेत्र क्रियान्वयन में फोन वॉट्सऐप और ज़ूम कॉलों पर आधारित ऑनलाइन सहभागिता वाला मॉडल अपनाया गया। हमने एवी संसाधनों को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को नए सिरे से डिज़ाइन भी किया।

लॉकडाउन के समय में, हमारे कार्यक्षेत्र वाले समुदायों में अन्य कई चिंताओं में भी बढ़ोत्तरी देखी गई। प्रोग्राम के प्रतिभागियों द्वारा घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के अनेक मामलों की रिपोर्ट की गई जो अपने लिए कानूनी, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहयोग चाहते थे - अपने पार्टनरों से मिलने का प्रयास करने के दौरान समुदाय के सदस्यों से हिंसा का सामना करने वाले किशोरों और युवा लोगों के मामले भी बढ़े। अनेक किशोर और युवा लोगों ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (एसआरएचआर) उत्पादों और सेवाओं, खासतौर से सैनिटरी नैपकिन, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों (ईसीपी), और गर्भपात सेवाओं तक पहुँच के लिए सहयोग माँगी। प्रतिदिन सामुदायिक मामलों का सामना करने के परिणामस्वरूप होने वाली थकान और तनाव का सामना करने के लिए सुविधादाताओं ने मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग की ज़रूरत भी बताई। लॉकडाउन लागू होने के दौरान समुदायों में जाति आधारित भेदभाव के मामलों को, समुदायों पर कोविड के प्रभाव पर चर्चा के दौरान क्षेत्र के सुविधादाताओं द्वारा साझा किया गया। अप्रैल से जून 2020 के पूरे समय में हमने समुदाय की विशेष कोविड संबंधी ज़रूरतों का आकलन किया और लॉकडाउन अवधि के दौरान संकटग्रस्त समुदायों के लिए राहत कार्यों में सहयोग के लिए संसाधन आवंटित कर सके। [17]

उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के संबंध में टीवाईपीएफ के अध्ययन और सहभागिता ने ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइनों की ज़रूरत प्रकट की जो जेंडर, यौनिक्ता, जाति, वर्ग, धर्म और सक्षमता के आधार पर उनकी मिली-जुली वास्तविकताओं के समाधान कर सकें। [18] चूंकि महामारी ने पुरुषों और लड़कों के जीवन को भी अत्यधिक प्रभावित किया, इसलिए यह समझना अनिवार्य है कि किस तरह से उनके लिए पहले से चालू प्रोग्रामों ने इन बदलती वास्तविकताओं पर किस तरह प्रतिक्रिया की। इसलिए, यह अध्ययन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ऐसे प्रोग्रामों की भविष्य में डिलीवरी को सूचित करने तथा प्रोग्राम लागू करने वालों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर पूर्वतैयारी सक्षम बनाने के लिए, विविध मसलों पर युवा पुरुषों और लड़कों के लिए कार्यशील विकास प्रोग्रामों पर कोविड-19 का प्रभाव समझने पर प्रमुख रूप से केंद्रित है।

17 वाईपी फाउंडेशन। (2020)। यूथ इनसाइट : इनफार्मिंग कोविड-19 रिलीफ एंड रिस्पांस विद यंग पीपुल्स एक्सपीरियंसेज।
18 वाईपी फाउंडेशन। (2019)। मर्दों वाली बातें: ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेन मस्क्युलिनिटीज एंड एसआरएचआर ।

अध्ययन की रचना

क्रियाविधि

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य युवा पुरुषों और लड़कों (14-25 वर्ष) के साथ कार्यक्रमों पर कोविड-19 का प्रभाव समझना था, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में काम करने वाली 17 संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के इंटरव्यू लिए गए। इस अध्ययन में एक गुणात्मक डिज़ाइन को इसकी खोजपूर्ण प्रकृति के कारण अपनाया गया, और नमूनों के लिए उद्देश्यपूर्ण और स्नोबॉल विधियां अपनाई गईं। संस्थाओं को उनकी विषय और स्थान के आधार पर चुनने के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श का उपयोग किया गया। विभिन्न विषयों में दृष्टिकोणों और अभ्यासों में अधिकतम विविधताओं को शामिल करने के लिए, अध्ययन में विविध संस्थाओं और इन संस्थाओं के विविध हितधारकों को भी चुना गया। स्नोबॉल प्रादर्श विधि से लागत और समय की बचत करते हुए विविध संस्थाओं तक पहुँचने में मदद मिली।

अध्ययनकर्ताओं द्वारा इन-डेप्थ इंटरव्यू का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने महामारी के पहले चरण के दौरान जमीनी स्तर पर कार्य करने के उनके अनुभव साझा किए। प्रत्येक इंटरव्यू 40-60 मिनट तक चला और इसे पहले से डिजाइन की गई सेमी-स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड की सहायता से किया गया था (परिशिष्ट देखें)। अध्ययन टीम और उत्तरदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सभी इंटरव्यू गूगल मीट या ज़ूम का प्रयोग करके या मोबाइल फोन पर कांफ्रेंस कॉल के माध्यम से आयोजित किए गए।

वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों से सीधे संपर्क के द्वारा, संस्थाओं के अध्ययन के उद्देश्य के बारे में भी सूचित किया गया। भागीदारी में रुचि रखने वाली संस्थाओं से एक फील्ड कार्यकर्ता और कोऑर्डिनेटर/मैनेजर नियमित करने के लिए कहा गया। इसके बाद, अध्ययन टीम ने हर एक नामित सदस्य से संपर्क किया और उनकी भागीदारी की पुष्टि की। इन-डेप्थ इंटरव्यू तय किए गए और भागीदार सदस्यों को सहमति का फार्म दिया गया। इन इंटरव्यूओं को उत्तरदाताओं की लिखित और मौखिक सहमति सहित रिकॉर्ड किया गया और विश्लेषण करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसक्राइब किया गया।

फील्ड कार्यकर्ता के इंटरव्यू लेकर अध्ययनकर्ता, समुदायों से उनके सीधे संपर्क के आधार पर, समुदायों पर लॉकडाउन के प्रभाव को समझ सके। इस तरह से, इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आजीविका, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा और हिंसा आदि से जुड़े मुद्दों का उपयोग किए गए। संस्थाओं के सामने आने वाली प्रोग्राम संबंधी चुनौतियों और समस्याओं की पूरी जानकारी के लिए, कोआर्डिनेटरों/मैनेजरों के इंटरव्यू लिए गए। इसके लिए व्यवधान, चुनौतियां, नीतियां और ऑनलाइन अनुकूलन आदि कोड उपयोग किए गए। लॉकडाउन के कारण संस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनका सामना करने के लिए प्रयोग की गई रणनीतियों में तुलना और अंतर समझने के लिए संस्थाओं की विषय आधारित सहभागिता का उपयोग किया गया।

अध्ययन आयोजन के दौरान विविध नैतिक नियमों का पालन किया गया। इंटरव्यू से पहले, सभी प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्यों और पृष्ठभूमि सहित पूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा, प्रतिभागियों को एक कांसेप्ट नोट और सहमति का फार्म भी दिया गया। सहमति फार्म में अध्ययन की प्रक्रिया तथा उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अध्ययन टीम द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया गया। सहमति फार्म वापस मिल जाने पर ही अध्ययन टीम ने इंटरव्यू शुरू किए। प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया गया कि उनको भागीदारी से मना करने या किसी विशेष प्रश्न का उत्तर न देने की स्वतंत्रता है और ऐसा करने पर कोई दंड नहीं लागू है। इसके अलावा, प्रतिभागियों के हित सुरक्षित रखने के लिए अध्ययन के टूल्स और प्रस्ताव को सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआरआई) के इंस्टीट्यूशनल रिव्यु बोर्ड द्वारा देखा और मंजूर किया गया।

सीमाएं

अध्ययन आयोजन के दौरान विविध सीमाओं की पहचान की गई। चूंकि डेटा संकलन ऑनलाइन किया गया था, इसलिए फोन और इंटरनेट तक पहुँच वाली संस्थाओं को ही अध्ययन में शामिल किया जा सका। इस कारण से, अध्ययन के निष्कर्ष पूरे उत्तर प्रदेश भर में काम करने वाले सीएसओ पर लागू होने अनिवार्य नहीं हैं और केवल उभरते रुझानों का संकेत दे सकते हैं। दूसरी बात, हालांकि अध्ययन का विषय आधारित दायरे को बढ़ाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य या क्वीर अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर युवा पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने वाली संस्थाओं को इंटरव्यू करने की कोशिश की गई, इस समयसीमा में ऐसी संस्थाओ को पहचाना नहीं जा सका जो टीवाईपीएफ के नेटवर्क में खासतौर से युवा पुरुषों और लड़कों के साथ इन मुद्दों पर काम करते हैं। तीसरी बात, चूंकि केवल ।7 संस्थाओं का इंटरव्यू किया गया अतः इस रिसर्च से प्राप्त सूचना पूरे भारत या यूपी पर आमतौर से लागू नहीं की जा सकती। हालाँकि, इस विश्लेषण से उभरकर सामने आने वाले व्यापक पैटर्न, प्रोग्रामों को उन तरीकों के बारे में सूचित कर सकेंगे, जिनसे भविष्य में प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करने में मदद मिलेगी। आखिरी बात, चूंकि ज़्यादातर इंटरव्यू हिंदी में लिए गए, इसलिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान कुछ डेटा का नुकसान हुआ हो सकता है।

इंटरव्यू लिए जाने वाले संस्थाओं की बैकग्राउंड

इस अध्ययन के लिए इंटरव्यू में शामिल 17 संस्थाओं में से नौ, कोविड-19 संकट से पहले जेंडर से संबंधित विषयों पर काम करते थे जैसे कि मर्दानगी, एसआरएचआर, जीबीवी, यौनिक्ता के अधिकार और बाल विवाह। इन 9 संस्थाओं में से चार एक साथ अभियान [19] में काम कर रहे थे जबकि अन्य पाँच संस्था स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। अन्य 8 संस्था आजीविका और रोजगार, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण और पलायन आदि मुद्दों के संबंध में वयस्क पुरुषों और लड़कों के साथ काम कर रहे थे।

तालिका 1 - संस्थाओं की विषय आधारित सहभागिताएं

क्र.सं.	सहभागिता की विषय	संस्थाओं की संख्या	विवरण
1.	जेंडर-संबंधित विषयों पर केंद्रित संस्था	9	थीमें, जैसे कि मर्दानगी, एसआरएचआर, जीबीवी, यौनिक्ता के अधिकार और शीघ्र, बाल्य और बाल विवाह। चार, एक साथ अभियान के अंतर्गत कार्य करते थे, जबकि अन्य पाँच संस्था स्वतंत्र रूप से से काम कर रहे थे।
2.	अन्य विषयों पर केंद्रित संस्था	8	• आजीविका और रोजगार - 4 • जल और स्वच्छता - 1 • स्वास्थ्य और पोषण - 2 • स्वच्छता - 1
	TOTAL	17	

तालिका 2: कोविड-19 लॉकडाउन से पहले संस्थाओं की रूपरेखा और कार्य

प्रतिभागियों के रूपरेखा	मुख्य गतिविधियां और सहभागिताओं की रणनीतियां	परिणाम और प्रभाव
• लगभग 10 संस्थाओं ने बताया कि वे एससी/एसटी समुदायों के बीच काम कर रहे थे जबकि 8 संस्थाओं ने बताया कि वे मुस्लिम युवाओं के बीच काम कर रहे थे।	• समुदायों के बीच जेंडर और यौनिक्ता जैसे मुद्दों के बारे में घर-घर जाकर अभियानों और समुदाय प्रेरित सत्रों के माध्यम से हर एक-दो सप्ताह में एक बार प्रोग्रामिंग को प्रत्यक्ष लागू किया जाना	• तकनीकी सहायता और ज्ञान देते हुए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी सेवाओं तक पहुँच मज़बूत बनाना।

19 एक साथ अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ, संगठनों का समूह है जो वयस्क पुरुषों और लड़कों के साथ कार्य करते हुए जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। https://www.eksaathcampaign.net/

निष्कर्ष और विश्लेषण

उभरती ज़रूरतें और बढ़ते संपर्क

17 संस्थाओं में से 14 ने बताया कि उन्होंने अपने समुदायों में सीधे राशन वितरित करने के लिए अपने फंड लगा दिए। अन्य 3 संस्थाओं में से एक संस्था ने अनौपचारिक रूप से (संस्था के स्टाफ द्वारा निजी दान का उपयोग करते हुए) समुदायों में राशन वितरण के बारे में बताया, एक संस्था ने पीडीएस के तहत मौजूदा राशन तक समुदायों की पहुँच मज़बूत बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे कि प्रधानों के साथ मिलकर काम करने के बारे में बताया, जिसके द्वारा समुदाय के उन सदस्यों को राशन की ज़रूरत वाले फार्म भरने में मदद दी गई, जिनको सरकार द्वारा अधिकृत राशन कार्ड नहीं दिया गया था और एक संस्था ने, बेघर लोगों के लिए पका हुआ भोजन बांटने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने के बारे में बताया। इस समय राशन के वितरण ने भी फील्ड वर्करों और समुदायों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाया।

> **कोविड के समय हमने विचार किया और [राशन का] वितरण किया। यह एक गरीब इलाका है और बहुत से लोगों को भोजन जुटाने में कठिनाई होती थी। और स्थिति इतनी खराब थी कि अब तक लोग भोजन का अनुरोध लेकर हमारे संस्था के पास आते हैं। यह लोगों के लिए हमारे संस्था को पहचानने का एक जरिया बन गया।**
>
> - फील्ड कार्यकर्ता

लगभग सभी उत्तरदाता संस्थाओं ने समुदायों को कोविड-19 से संबंधित रोकथाम वाले उपाय अपनाने में सक्षम बनाने के लिए, अपने समुदायों में मास्क और सैनेटाइजर बांटने का काम किया और इसके अलावा मेडिकल सप्लाई का एक पैकेज भी बांटा गया जिसमें साधारण जुकाम व बुखार के इलाज में काम आने वाली ओवर दि काउंटर बिकने वाली दवाएं जैसे कि पैरासिटामॉल थीं। हालाँकि, कुछ मामलों में, कोविड-19 के बारे में सही जानकारी के अभाव की वजह से फील्ड स्टाफ को समुदाय के सदस्यों की तरफ से अविश्वास का भी सामना लगभग सभी उत्तरदाता संस्थाओं ने समुदायों को कोविड-19 से संबंधित रोकथाम वाले उपाय अपनाने में सक्षम बनाने के लिए, अपने समुदायों में मास्क और सैनेटाइजर बांटने का काम किया और इसके अलावा मेडिकल सप्लाई का एक पैकेज भी बांटा गया जिसमें साधारण जुकाम व बुखार के इलाज में काम आने वाली ओवर दि काउंटर बिकने वाली दवाएं जैसे कि पैरासिटामॉल थीं। हालाँकि, कुछ मामलों में, कोविड-19 के बारे में सही जानकारी के अभाव की वजह से फील्ड स्टाफ को समुदाय के सदस्यों की तरफ से अविश्वास का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए विविध लोकेशनों पर, समुदायों ने इस डर की वजह से राहत सामग्री को स्वीकार नहीं किया कि इससे कोविड-19 हो सकता है और एक संस्था ने यह भी बताया कि "बाहरी" लोगों के जरिए कोविड-19 फैलने के भय की वजह से ज़्यादातर फील्ड वर्करों को गाँवों में जाने नहीं दिया जाता था। संस्थाओं के स्टाफ को लेकर ऐसी धारणा की वजह से, हिंसा से संबंधित हस्तक्षेप वाले प्रयासों के लिए पहले से मौजूद प्रतिरोध और भी प्रबल हो गया, जहां हिंसा को “आंतरिक”

मामला माना जाता है जिसमें 'बाहरी' लोगों का दखल मंजूर नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में, कुछ मामलों में संस्थाओं के स्टाफ और समुदायों के बीच रिश्तों पर कोविड-19 संकट की वजह से भी नकारात्मक असर पड़ा।

युवा पुरुषों और लड़कों के बीच जेंडर, हिंसा और रोजगार जैसे मसलों पर काम करने वाली संस्थाओं ने खासतौर से यह बताया कि युवा पुरुषों और लड़कों के साथ अपनी चर्चाओं की विषयवस्तु में बदलाव करते हुए उन्होंने कोविड-19 संबंधित जागरूकता सृजन, कोविड-19 सुरक्षा उपायों और नियमों के बारे में जानकारी देने और प्रतिभागियों के समुदायों पर इस संकट के प्रभावों पर चर्चा को शामिल कर यिा, ताकि समुदायों की उभरती ज़रूरतों का आकलन किया जा सके और उसी के हिसाब से संसाधन वितरित किए जा सकें। मर्दानगी के मसले पर काम करने वाली एक संस्था ने, पहले अनलॉक की घोषणा के बाद यू.पी. के विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य शिविर भी स्थापित किए। यह कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने, समुदायों की तात्कालिक ज़रूरतों पर और इनके समाधान के लिए किए जा सकने वाले संभावित राहत उपायों पर चर्चा में भाग लेने के लिए समुदायों और राज्य के आपातकालीन हेल्पलाइन वर्करों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए किया गया। इन स्वास्थ्य शिविरों से समुदायों में कोविड-19 संबंधित आपातस्थितियों के लिए हेल्पलाइन मौजूद होने के बारे में जानकारी देने में भी मदद मिली। संस्थाओं ने परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देने और घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए भी हेल्पलाइनें स्थापित कीं। गर्भनिरोधकों जैसे कि कंडोम और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों और मासिक स्राव स्वच्छता उत्पादों जैसे कि सैनेटरी पैड तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भी हेल्प डेस्कें स्थापित की गईं। इन हेल्पडेस्कों की मौजूदगी के बारे में सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया गया और वॉट्सऐप के माध्यम से आंतरिक नेटवर्कों में जानकारी फैलाई गई।

संस्था, प्रतिभागियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को लेकर भी सतर्क और संवेदनशील थे और ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे कि ज़ूम/गूगल मीट पर मजेदार गोष्ठियों और इंटरएक्टिव गतिविधियों के आयोजन किए गए। पूरे लॉकडाउन के दौरान, स्टाफ सदस्यों और संस्थाओं ने समुदायों से वॉट्सऐप और फोन कॉलों के जरिए संपर्क बनाए रखा और इन चैनलों के माध्यम से, जीबीवी के नए मामलों पर प्रतिक्रियाएं कीं। संस्थाओं ने बताया कि जीबीवी के अनेक मामलों में उनके द्वारा पुलिस के दखल का अनुरोध किया गया था। कुछ संस्थाओं ने, जीबीवी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए पुलिस के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ इस दौरान क्षमता सृजन के सत्र भी आयोजित किए। परिवारों में विवादों के समाधान के लिए उन्होंने काउंसिलिंग के तरीके का भी उपयोग किया।

"क्या आप मुझे सुन सकते हैं?" : "नए नार्मल" को अपनाना

लॉकडाउन लगने के बाद, संस्थाओं द्वारा फोन कॉलों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों की तात्कालिक ज़रूरतों का आंकलन किया गया। समुदायों के अन्य हितधारकों जैसे, ग्राम प्रधानों, स्थानीय सरकारी कर्मचारियों या स्वास्थ्य-कर्मियों से संपर्क में बने रहने के लिए भी टेलीफोन कॉलों का इनोवेटिव तरीके से उपयोग किया गया। अध्ययन के दौरान अनेक उत्तरदाताओं ने बताया की उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने प्रोग्राम संबंधी कार्यों को ऑनलाइन मंचों, जैसे कि ज़ूम/गूगल मीट, पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा था।

फलस्वरूप, देशव्यापी लॉकडाउन को कई बार बढ़ाए जाने और बाद में क्रमानुसार अनलॉक किए जाने के साथ, संस्थाओं को समुदायों के साथ अपनी सहभागिता की रणनीतियों में बड़े बदलाव करने पड़े। परिणामस्वरूप, अनेक संस्थाओं ने अपनी ज़मीनी हस्तक्षेप की गतिविधियों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे कि ज़ूम, गूगल मीट या वॉट्सऐप पर शिफ्ट कर लिया और अपनी ज़मीनी गतिविधियों को पाठ्यक्रमों और शिक्षाविधि रिवीज़न के माध्यम से वर्चुयलप्लेटफार्मों पर काम करने के लिए अनुकूलित बनाया। मेजबान समुदायों से बातचीत करने के बाद यह रिवीज़न किए गए, ताकि उनके माध्यम से कोविड-19 से संबंधित उभरते मसलों को विषयवस्तु में शामिल किया जा सके। युवा पुरुषों और लड़कों के बीच, जेंडर और मर्दानगी से संबंधित कार्य करने वाली संस्थाओं ने अपने प्रतिभागियों को जोड़े रखने के लिए ऑडियो-विज़ुअल संसाधन तैयार किए। यह ए० वी० संसाधन वॉट्सऐप के माध्यम से साझा किए गए और वॉट्सऐप समूहों में या ज़ूम/गूगल मीट पर ऑनलाइन बैठकों मे इन संसाधानो के ज़रिए सामूहिक चर्चाएं कराई गईं।

ग्रामीण उत्तर प्रदेश के संस्थाओं के साथियों ने बताया कि उन्होंने अपने समुदायों के साथ अपने निर्धारित कार्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए अनुकूल बनाने के दौरान कुछ तत्काल चुनौतियों का सामना किया। अनेक समुदायों में स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं थे, जिसके कारण उन्हें ऑनलाइन बैठकों में भाग लेने मे कठिनाई हुई। गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने की वजह से ज़ूम/गूगल मीट पर बैठकें कराना असंभव था। ऑनलाइन बैठकों और सत्रों में प्रतिभागियों की रुचि का आकलन कर पाना, ख़ास तौर से कठिन था। कुछ संस्थाओं ने यह भी बताया कि फंडर्स द्वारा कड़ी समय-सीमाएं लागू किए जाने की वजह से कुछ प्रोग्रामों की ऑनलाइन या फोन कॉलों द्वारा निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया ज़रूरी हो गई थी।

इन संस्थाओं ने इन चुनौतियों को कम करने के लिए अपनाए गए विशेष उपायों के बारे में भी बताया। उदाहरण के लिए, शिक्षा के मसले पर काम करने वाली संस्थाओं ने गैजेट्स तक अपने प्रतिभागियों की पहुँच के अभाव को देखते हुए, समुदाय में आसपास रहने वाले ऐसे पांच प्रतिभागियों के समूह बनाए, जिनमें से एक के पास स्मार्टफोन था। जेंडर के मसले पर काम करने वाली एक अन्य संस्था ने अपने प्रतिभागियों को, अनलॉक के बाद फोन और टेबलेट उपलब्ध कराए और अपने प्रतिभागियों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता के साथ ऑनलाइन शिष्टाचार भी सिखाया। कोविड-19 के बारे में जानकारी फैलाने या विभिन्न मसलों पर दृश्य-श्रव्य संसाधन साझा करने के लिए अनेक संस्थाओं ने वॉट्सऐप ग्रुप बनाए और उनका उपयोग किया, ताकि इंटरनेट की कठिनाई होने के बावजूद भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली एक संस्था ने एक ऐसा वॉट्सऐप ग्रुप बनाया जिसमें एक काउंसलर को शामिल किया गया, ताकि कोविड-19 के बारे में प्रमाणिक जानकारी सुलभ कराई जा सके।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं ने अपने समुदायों में तकनीक और गैजेट्स तक बेहतर पहुंच बनाने की पहल पर उनका अनुभव साझा किया। इन संस्थाओं के लिए, इनके प्रोग्रामों के प्रतिभागी ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर प्रोग्राम संबंधित गतिविधियों को शिफ्ट करने के मामले में अग्रणी रहे। उदाहरण के लिए, दो संस्थाओं ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने उन प्रतिभागियों की मदद से टिकटॉक पर शिफ्ट किया जो इस प्लेटफार्म से पहले से बखूबी परिचित थे। हालांकि, जब सरकार ने विविध चरणों में अनलॉक किए जाने की घोषणाएं शुरू कर दीं तो ऑनलाइन कार्य धीरे-धीरे कम होने लगा और जून 2020 तक ज़्यादातर संस्था फील्ड पर वापस पहुँचने लगे।

प्रोग्रामिंग बैकसीट पर

"एक साथ अभियान" में काम करने वाली एक संस्था के अनुसार,[20] पलायन या आजीविका - आधारित मज़बूरियों के कारण प्रोग्राम के प्रतिभागियों का छूट जाना, सहभागिता के सभी वर्षों में हमेशा ही एक समस्या रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। प्रोग्रामों में इन बाधाओं के असर को कम करने के लिए संस्थाओं ने सदैव ही अपने प्रतिभागियों से बातचीत के माध्यम बनाए रखने की कोशिशें कीं; शहेरो में पलायन कर गए प्रतिभागियों के साथ भी नियमित रूप से संपर्क में रहें।, यह रणनीति/ पहल लॉकडाउन की अवधि में प्रवासी कामगार को राहत सहायता प्रदान करने में उपयोगी साबित हुए। साथी ही, लॉकडाउन ने प्रतिभागियों के प्रोग्रामों को छोड़कर चले जाने वाली घटनाओं को और भी गंभीर बनाया, क्योंकि उनको आमदनी और रोज़गार के नुकसान की भरपाई करने की तत्काल ज़रूरत थी और उनको अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए कई प्रकार के काम करने पड़ते थे। इसके अलावा, जहां शहरों से प्रवासी कामगार के पलायन ने ग्रामीण इलाकों में विकास प्रोग्रामों में शामिल प्रतिभागियों की तादाद बढ़ा दी, वहीं इस जनसंख्या की मौजूदगी को अल्पकालीन माना गया। कार्यकर्ता भी इन संस्थाओं से जुड़ने के इच्छुक नहीं थे; क्योंकि उनको पता था कि यह सहभागिता थोड़े वक्त तक ही चल पाएगी। जब अर्थव्यवस्था फिर से, लॉकडाउन से पूर्व पहले की तरह, पटरी पर लौट आएगी तब शहरों में उनकी नौकरियां उनको वापस मिल जाएँगी। शहरी मलिन बस्तियों में काम करने वाली एक संस्था ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हुआ पलायन - लॉकडाउन के दौरान शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों की तरफ और लॉकडाउन के बाद ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ -यह कोविड-19 के दौरान काम करते समय सबसे बड़ी चुनौती बनी।

इसे अवश्य याद रखा जाना चाहिए कि जहां अधिकांश संस्थाओं ने कोविड-19 संकट के कारण समुदायों में युवा पुरुषों और लड़कों की आजीविकाओं पर नकारात्मक प्रभाव की वजह से प्रोग्रामों में ड्रॉप-आउट की ऊंची दरों की बात बताई, वहीं मर्दानगी और जेंडर संबंधित प्रोग्रामों में ड्रॉप-आउट की दरें, अन्य विषयों पर आधारित प्रोग्रामों से अधिक पाई गईं। संस्थाओं के अनुसार इसके दो कारण समझे जा सकते हैं - पहला, जेंडर और मर्दानगी के मसलों पर काम करने वाली संस्थाओं ने, लॉकडाउन और अन्य संबंधित आकस्मिक स्थितियों की वजह से बीच में लंबे ब्रेक के कारण अपनी सहभागिताओं को प्रमुख रूप से ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। जैसा कि पहले कहा गया है, ऑनलाइन सहभागिताएं तकनीकी मसलों से घिरी थीं, जिससे बहुत से प्रतिभागियों को प्रोग्रामों से बाहर होना पड़ा। दूसरा, प्रोग्राम लागू किए जाने के बीच में ब्रेक आने की वजह से रिफ्रेशर सत्रों की ज़रूरत हुई, जो प्रतिभागियों को अक्सर दोहराव और बोरियत भरे लगे, जिससे प्रतिभागिता और उपस्थिति की दरें कम हो गईं। अंत में, आजीविका खोजने और उसे बनाए रखने की ज़रूरत को प्राथमिकता देने के कारण प्रोग्रामों से प्रतिभागियों की सहभागिता छूटती गई।

20 एक साथ अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ, संगठनों का समूह है जो वयस्क पुरुषों और लड़कों के साथ कार्य करते हुए जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। https://www.eksaathcampaign.net/

विषयगत सहभागिताओं पर प्रभाव

I. आजीविका

आजीविकाओं और कमाई के साधनों का नुकसान, कोविड-19 महामारी के कारण सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती थी। इस अनुसंधान कार्य के लिए इंटरव्यू किए जाने वाली 17 संस्थाओं में से, 9 संस्थाओं के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन का एक गंभीर प्रभाव, उनके कार्यक्रमों में शामिल युवा पुरुषों और लड़कों के आजीविका और रोजगार पर पड़ा।। प्रतिभागियों की सामाजिक-आर्थिक पहचानों के अनुसार यह प्रभाव, दैनिक वेतन वाले मजदूरों, जैसे कि पटरी दुकानदारों और कंस्ट्रक्शन वर्करों तथा सैनिटेशन वर्करों और प्रवासी कामगारों के मामलों में खासतौर से देखा गया।

लॉकडाउन से पहले, आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं का एक प्राथमिक केंद्र मनरेगा स्कीम के माध्यम से रोजगार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना था। लॉकडाउन अवधि के दौरान भारी बेरोजगारी को देखते हुए, समुदायों को संकट का सामना करने में सहयोग करने के लिए यह कार्य पहले से और ज़रूरी हो गया था। हालाँकि, जैसा कि उत्तरदाताओं ने बताया, कि लॉकडाउन के दौरान एक योजना के तौर पर मनरेगा लगभग निष्क्रिय रही थी।

इसके अलावा, यात्राओं और आवाजाही पर प्रतिबंधों ने संस्थाओं के लिए फील्ड विजिट करने और जॉब कार्ड पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ भरने में अपने समुदायों की सहायता करने की क्षमता सीमित कर दी थी। हालाँकि उत्तरदाताओं ने अपने प्रतिभागियों से फोन कॉलों के जरिए अपना संपर्क सुनिश्चित किया, लेकिन उनके लिए पूरे कार्यक्रम का ऑनलाइन माध्यम पर अनुवाद करना एक बड़ी चुनौती बनता दिखा। उत्तरदाता लॉकडाउन के बाद ही फील्ड में विजिट कर सके, उस समय तक रोगजार और आजीविका के अवसरों की ज़रूरत कई गुना बढ़ चुकी थी। इस कारण, महामारी की पहली लहर के दौरान आजीविकाओं पर कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं पर और दबाव बढ़ गया था।

कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिभागियों के जीवन पर होने वाले अ-समान प्रभाव, आजीविकाओं पर कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर सामने आया। उत्तरदाताओं ने बताया, कि सीमांत जातियों के युवा पुरुषों के साथ जाति आधारित भेदभाव किया जा रहा था, जिससे उनके आजीविका के अवसर प्रभुत्वशाली जाति वाले समुदायों के युवा पुरुषों के मुकाबले और भी अधिक प्रभावित हुए थे। उदाहरण के लिए, सफाई कर्मचारियों (सैनिटेशन वर्करों) के साथ काम करने वाली एक संस्था ने बताया कि उनके प्रोग्राम के प्रतिभागियों को उन इमारतों और अपार्टमेन्ट परिसरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां वे महामारी से पहले काम किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन भवनों के निवासी और आरडब्ल्यूए सफाई कर्मचारियों को अस्वच्छ मानते थे और अस्वच्छता को कोविड-19 की आशंका को बढ़ाने से संबंधित माना गया। इससे पता चला कि जहां महामारी के दौरान सभी समुदायों के वर्करों की आजीविकाओं और नौकरियों का नुकसान हुआ वहीं इसके कारणों का निर्धारण मौजूदा जाति क्रम व्यवस्था द्वारा किया गया था।

इसी प्रकार से, प्रतिभागियों के बीच वर्ग और लोकेशन के अनुसार अंतर भी एक चुनौती बनकर उभरे। उत्तरदाताओं ने बताया कि शहरों में युवा पुरुष, खासकर प्रवासी कामगार ज्यादा कमाई वाली नौकरियां करते थे और इसलिए वे गाँवों में कम आय वाले काम करने के इच्छुक नहीं थे।

> "ज़्यादातर लोगों ने शहरों में अपनी आजीविकाएं गंवा दीं, जिस कारण लोगों को वापस माइग्रेट करना पड़ गया। जो लोग बाहर 15000 से 25000 तक रुपये कमा रहे थे, वे मनरेगा के तहत या खेतों में काम करने के इच्छुक नहीं थे। एक समस्या ये थी कि उस समय नौकरियों के तौर पर मनरेगा ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प था, जो पहले से ही कम थीं।"
>
> - कोआर्डिनेटर

जैसा कि संस्थाओं ने बताया, कि आजीविकाओं और रोजगार के अवसरों के अत्यधिक नुकसान के कारण उन समुदायों में जीबीवी में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई, जहां वे अपने प्रोग्राम चलाते थे। उत्तरदाताओं के अनुसार, आजीविकाओं और रोजगार के नुकसान ने उनके प्रोग्रामों में प्रतिभागियों को ज़्यादा चिड़चिड़े, व्याकुल और हिंसक बना दिया, जिससे घरेलू परिवेश में वाद-विवाद और शारीरिक हिंसा का बोलबाला हो गया, जिसका शिकार प्रायः उनके जीवनसाथी को होना पड़ता था। अनेक संस्थाओं ने कहा कि पितृसत्तात्मक शक्ति का दबदबा बनाए रखने के साधन के तौर पर हिंसा ने, आजीविकाओं की निरंतर कमी की वजह से और भी गंभीर रूप ले लिया। और इस समझ के आधार पर उन्होंने जीबीवी के मामले सूचित करने वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशन या रोजगार के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को केंद्रित किया।

II. शिक्षा

इंटरव्यू में शामिल संस्थाओं के मुताबिक, प्रोग्रामों में शामिल किशोर युवाओं के लिए लॉकडाउन का नतीजा शिक्षा में बाधा के रूप में सामने आया। हालांकि संस्थाओं ने महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर खासतौर से बुरे प्रभाव की बात की, लेकिन युवा पुरुषों और लड़कों की ड्रॉप-आउट की दरें भी काफी अधिक पाई गईं। संस्थाओं के अनुसार इन ड्रॉपआउट की वजह गहराई में जेंडर से जुड़ी थी-जहां यह बताया गया कि घरेलू कामकाज में सहायता के लिए युवा लड़कियों को स्कूलों से निकाल लिया गया, वहीं युवा पुरुषों और लड़कों की पढ़ाई छूटने का कारण यह बताया गया कि उनको तुरंत किसी रोजगार में लगकर अपने परिवारों की वित्तीय मदद करनी थी। लखनऊ में काम करने वाली एक संस्था ने बताया कि किस तरह से इस समय के दौरान लड़कों ने अपने परिवारों की सहायता के लिए धन कमाने के नए-नए तरीके खोजे, जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन के साथ समुदायों में भोजन और राशन पहुँचाना और, फूड पैकेजिंग उद्योग में काम करना। ये कार्य काफी थकाऊ थे, इसके लिए युवा पुरुषों और लड़कों को प्रायः दिन भर कई-कई शिफ्टों में काम करना पड़ता था।

जिन लोगों को तनाव और निर्धनता के कारण स्कूल नहीं छोड़ने पड़े, उनके मामले में, जैसा कि संस्थाओं ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं ने उन छात्रों के लिए परिस्थितियां गंभीर बना दीं, जो किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके के छात्रों ने शहरी छात्रों की तुलना में ज़्यादा समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि उनके सामने तकनीक तक पहुँच और उपलब्धता, डेटा पर आधारित अध्ययन सामग्री तथा प्रोफेसरों से एकतरफा संवाद जैसी समस्याएं अधिक थीं।

> ""हमारे कार्य वाले समुदायों में ज़्यादातर दैनिक मज़दूर, रिक्शाचालक और सब्ज़ी विक्रेता शामिल हैं, जिन सभी पर कोविड-19 के कारण बड़ा नकारात्मक असर पड़ा। उनके रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो गई। उच्च आय वाले समूहों के बच्चों के पास स्मार्टफोन थे और उनकी शिक्षा जारी रही। लेकिन कम आय समूहों के लिए लॉकडाउन ने उनकी शिक्षा को समाप्त कर दिया।"
>
> - फील्ड कार्यकर्ता

> "हमारे संपर्क वाले शिक्षकों और वालंटियर्स ने वॉट्सऐप के जरिए संपर्क बनाए रखा और वे कोविड-19 के दौरान समुदायों में अपना काम करते रहे। इस काम में नामित प्रतिभागी, बहुत मज़बूत बैकग्राउंड वाले नहीं थे और वॉट्सऐप और अन्य एप्लिकेशनों तक उनकी पहुँच नहीं थी। डिजिटल संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं थी। इसलिए हमने शिक्षकों और वालंटियर्स से कोआर्डिनेट करने के लिए केवल वॉट्सऐप का उपयोग किया।"
>
> - कोआर्डिनेटर

जहां शहरी उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए बिजली और स्मार्टफोन की बेहतर सुलभता पाई गई, वहां ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याएं और लॉकडाउन के कारण उत्पन्न तनाव और असमंजस की वजह से कक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रों में रुचि का अभाव, ड्रॉपआउट की प्रमुख वजह रही।

इन चुनौतियों को देखते हुए, संस्थाओं ने शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तौर पर तीन तरीके अपनाए : छात्रों के लिए ज़रूरी स्टेशनरी, नोटबुक्स और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराना; मोहल्ला पाठशाला की व्यवस्था शुरू करना, जहां एक शिक्षक, छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं चला सके; एक शिक्षक नियुक्त करना, जिसका काम यह सुनिश्चित करना था कि सभी छात्र पढ़ रहे हैं और वह किन्हीं संदेहों का निवारण कर सके।

III. स्वास्थ्य

कोविड-19 के मामलों को प्राथमिकता देना, महामारी के समय स्वास्थ्यसेवा सेक्टर की प्रमुख प्रतिक्रिया थी। भारत सरकार ने 20 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि अस्पतालों में वाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) बंद रखे जाएंगे, गैर-चयनात्मक अनिवार्य ऑपरेशन स्थगित रहेंगे और कोविड-19 के रोगियों के लिए कुछ बेड रिजर्व रखे जाएंगे। इसका समुदाय के सदस्यों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जैसा कि विविध संस्थाओं ने बताया। पाँच संस्थाओं ने कहा कि इस समय अस्पताल जाने से एक सामान्य भय की भावना जुड़ गई थी, क्योंकि इस दौरान अस्पतालों को कोविड-19 का हॉटस्पॉट माना जाने लगा था। अन्य संस्थाओं ने भी बताया कि इस दौरान स्वास्थ्यसेवा सेक्टर तक आमतौर से पहुँच नहीं रह गई थी। चूंकि क्लीनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद थे, इसलिए रोगियों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना होता था, जहां रोगियों को अन्य साधारण समस्याओं जैसे कि टांगों में दर्द के लिए भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती थी। बताया गया कि इस समय जो रोगी किसी तरह डॉक्टरों से मुलाकात करने में

सफल हो पाते थे, उनके समुचित चेक-अप के बिना ही प्रायः डॉक्टर उनको दवाएं दे दिया करते थे। अनेक डॉक्टर संक्रमण के भय से अपने रोगियों को छूने या इंजेक्शन देने से मना कर देते थे, जैसा कि एक उत्तरदाता ने बताया, इस कारण से समुदाय में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी।

कोविड-19 संकट से पहले, युवा पुरुषों और लड़कों के बीच स्वास्थ्य समस्याओं पर काम करने वाली संस्था आशा और आंगनवाड़ी वर्करों के साथ पैरवी गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्यसेवा प्रावधानों तक पहुँच बेहतर बनाने का प्रयास करते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि स्थानीय सरकार की मौजूदा सेवाएं और स्कीमें, समुदायों के सबसे सीमांत सदस्यों की पहुँच में तथा उनके लिए किफायती बनी रहें। आशा और आंगनवाड़ी वर्करों के साथ यह पैरवी और सहभागिता लॉकडाउन के दौरान मज़बूत की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुदाय के सदस्य कोविड-19 के अलावा अन्य स्वास्थ्यसेवा ज़रूरतों के लिए स्थानीय अस्पतालों में पहुँच सकें। समुदायों की तात्कालिक ज़रूरतों की पहचान के लिए आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों के साथ सहयोग, मेडिकल सप्लाई के वितरण के लिए भी उपयोगी साबित हुआ।

संस्थाओं ने बीमार रोगियों को अस्पतालों तक पहुँचाने में भी मदद की और स्थानीय अस्पतालों में स्वास्थ्यसेवा अधिकारियों से संपर्क किया ताकि कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए लागू कड़ी प्रक्रियाओं में, जो समुदायों में नॉन-कोविड-19 रोगियों के लिए नुकसानदेह थीं, कुछ बदलाव किए जा सकें और स्थानीय सरकारी अधिकारियों से संपर्क रखकते हुए पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए दवाओं की उपलबधता और कीमतों के बारे में समुदायों को जागरूक करने काभी कार्य किया।

स्वास्थ्य- संबंधित मसलों पर युवा पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने वाली संस्थाओं ने, कोविड-19 से संबंधित चिंताओं के बारे में जागरूकता फैलाने की गतिविधियों को प्राथमिकता देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रसार या लक्षणों के बारे में सही जानकारी का न होना, युवा पुरुषों और लड़कों के लिए काफी तनाव और चिंता की बात थी। पूर्वी यूपी की एक संस्था ने बताया कि उनके समुदायों के पुरुषों ने वायरस फैलने के डर से अन्य समुदाय के सदस्यों से पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया, जिसमें उनके अपने परिवार के सदस्य भी शामिल थे। साथ ही, यूपी के अन्य भागों में पुरुषों में पॉजिटिव टेस्टिंग की वजह से बदनामी के कारण इसे लेकर भय देखा गया जिसके कारण समुदाय में लोगों को भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ सकता था। क्षेत्र में टेस्टिंग की कम दरों का यह एक प्रमुख कारण था। स्वास्थ्य पर काम करने वाली अधिकांश संस्थाओं ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और सही जानकारी देने और गाँवों में आईईसी सामग्रियां बांटने के लिए अपने समुदायों में डोर टू डोर अभियान चलाए, क्योंकि वॉट्सऐप ग्रुपों और फेसबुक के जरिए बहुत सारी भ्रामक जानकारियां इधर-उधर फैलाई जा रही थीं। संस्थाओं ने केवल वही जानकारी शेयर की, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित की गई थी।

IV. हिंसा और मर्दानगी

कोविड-19 के संकट से पहले, जेंडर समानता पर काम करने वाली संस्था, जेंडर, मर्दानगी, पितृसत्ता, यौन और प्रजनन स्वास्थ, और जेंडर आधारित हिंसा के बारे में बात करने के लिए पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकार आधारित विधि का उपयोग करते थे। वे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, मानव तस्करी और कम उम्र में और बाल विवाह से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों से पैरवी भी करते थे।

इनमें से ज्यादातर संस्थाओं ने बताया कि कोविड-19 महामारी और बाद में लॉकडाउन से पूर्व उनका कार्य चल रहा था। इसमें पैमाने, लोकेशन, विषय आधारित फोकस और संस्था के ढांचे आदि सभी का विस्तार हो रहा था। नई जगहों में काम को बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं सीधे एक गाँव का दौरा करती थीं और समुदायों से मिलकर ज़रूरतों का आकलन करती थीं। अन्य संस्थाओं ने बताया कि आधिकारिक ढांचों जैसे कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी प्रवेश करना उनके लिए उपयोगी होता था, क्योंकि इससे उन्हें अपने कार्य की मान्यता बढ़ाने में मदद मिलती थी। प्रोग्रामों से निकलकर सामने आने वाली सफलता की कहानियां, अन्य पुरुषों और लड़कों को भी शामिल होने के लिए प्रेरित करती थीं, जिनको व्यवहारिक बदलाव प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत और सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता था। समुदायों में विजिट करने वाले अधिकांश फील्ड कार्यकर्ता प्रायः इंटरएक्टिव सत्रों और खेलों के आयोजन करते थे जिनसे प्रतिभागियों को एक समझ बनाने करने में मदद मिलती थी। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य या बाल विवाह के मसलों पर आईईसी सामग्रियों का वितरण या लोगों के बड़े समूहों तक पहुंचने के लिए अभियान चलाना आदि सहभागिता के अन्य स्वरूपों में शामिल था।

लॉकडाउन खुलने के शुरुआती महीनों में, जेंडर और मर्दानगी पर पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने के मामले में, संस्थाएं मुख्य रूप से दो मुद्दों पर काम कर रहीं थी, पहला मुद्दा घर के कामों में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना था, यह देखते हुए कि पुरुषों और लड़कों को लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर बंद रहना पड़ रहा है। अनेक संस्थाओं ने बताया कि पुरुषों और लड़कों में घरेलू कामकाज को लेकर काफी हिचक पाई गई, क्योंकि इस कार्य को औरतों का काम माना जाता है। इसके अलावा, पुरुषों और लड़कों की आय के अभाव ने यह असुरक्षा और बढ़ा दी थी। संस्थाओं ने अपने प्रोग्रामों के प्रतिभागियों द्वारा घरेलू कामकाज में सहायता करने, जैसे कि पानी भरने, फर्श पर पोंछा लगाने और पढ़ाई में बच्चों की मदद करने आदि के कई उदाहरण बताए। सकारात्मक रोल मॉडलिंग का उपयोग करके, ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को घरेलू कामकाज में महिलाओं का हाथ बंटाने हेतु प्रेरित किया गया। हालाँकि, ऐसे अनेक उपायों के बावजूद घरेलू कार्य अब भी ज़्यादातर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। विविध मामलों में, संस्थाओं ने बताया कि पुरुषों ने घरेलू कामकाज को कार्य मानने से इनकार कर दिया और वे अक्सर विभिन्न कारणों से अपने पार्टनर पर चिल्लाते थे, जैसे कि समय पर खाना न मिलना, खाने का अभाव या यह मानते ही नहीं थे कि इस काम से उनके पार्टनर को भी थकावट हो सकती है।

आमतौर से ऐसे वाद-विवादों के बाद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ती पाई गई। डेटा से पता चला है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने की वजह से, पूरी दुनिया भर में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी गई है, क्योंकि पीड़ित लोग, अपने शोषणकर्ता के साथ अधिक समय तक साथ रहने रहने को मज़बूर हुए।[21] पुरुषों और लड़कों के साथ काम करने वाली संस्थाओं ने आजीविका, मर्दानगी और हिंसा के बीच एक बुनियादी संबंध स्थापित करते हुए बताया कि आजीविका के अभावों ने, घर में अपने दर्जे को लेकर पुरुषों के मन में चिंताओं में बढ़ोत्तरी कर दी। परिवार में अपना दर्जा और प्रभुत्व खोने का यह डर उत्पन्न होने की वजह से पुरुष अपने परिवार के सदस्यों से हिंसक व्यवहार करने लगे, ताकि वे उन पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकें। उदाहरण के लिए, महिलाओं को फोन पर बात करते और हंसते देखकर पुरुषों ने उनसे हिंसक व्यवहार किया, क्योंकि पुरुषों को आशंका थी कि उनकी पत्नियां उन्हें 'धोखा' दे रही हैं।

21 दि एसेंसियल्स फॉर रिस्पांडिंग टू वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स इन्यूरिंग एंड ऑफ्टर कोविड-19। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी (आईआरसी)। (2020, जून 29)। https://www.rescue.org/report/essentials-responding-violence-against-women-and-girls-during-and-after-covid-19.

"रोज कमाकर खाने वाले पुरुष इस समय में बहुत कठिनाइयों का शिकार हुए। उनको लगता था कि अब यह समय, महिलाओं का समय है। चूंकि वे घर पर थे, इसलिए अपने बारे में सोच को लेकर वे अधिक चिंतित थे।"

- फील्ड कार्यकर्ता

हालांकि, यह प्रतीत होता है कि संस्थाओं द्वारा यह संबंध बहुत शुरुआती स्तर पर देखा गया है और निष्कर्ष निकालने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता होगी। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि समुदायों में बढ़ते जीवीबी मामलों की एक वजह शराब का सेवन भी है। एक नज़रिए से, लॉकडाउन के दौरान शराब का न मिलना, घर में सुखशांति का कारण माना गया, जबकि दूसरी ओर इससे घरेलू हिंसा में और बढ़ोत्तरी हुई क्योंकि शराब न मिलने से इसके आदी पुरुष अपने घरों में चिड़चिड़े हो गए थे।

""पुरुषों में शराब पीने को लेकर बेचैनी थी और गाँवों में, केवल स्थानीय दुकानें खुलती थीं और केवल गन्ने से बनी देशी शराब ही उपलब्ध थी। तो, उनको कहीं न कहीं से शराब मिल ही जाती थी। और शराब की कीमत भी बढ़ गई थी। जो पी नहीं सकते थे, वे भी काफी परेशान रहते थे।"

- फील्ड कार्यकर्ता

जेंडर संबंधित मामलों पर काम करने वाली संस्थाएं ने यह भी बताया कि समुदायों में वैवाहिक बलात्कार के मामलों में बढ़ोत्तरी देखने-सुनने को मिली, जिसका संबंध उन्होंने पुरुषों के घर में खाली बैठे रहने से जोड़ा। संस्थाओं के अनुसार, पुरुषों ने लॉकडाउन को अपने पार्टनर से अपने रिश्ते 'सुधारने' के एक अवसर के रूप में देखा।

"हिंसा के मामले बढ़ गए, क्योंकि पुरुषों की नौकरियां चली गई थीं और वे घरों में खाली बैठे थे; पुरुष और महिलाएं, एक ही स्थान पर सीमित थे। इससे पहले किसान सुबह 7 बजे अपना कामकाज करने के लिए खेतों की ओर निकल जाते थे, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के बाद लोगों की नौकरियां चली गईं और दिन और रात के समय भी बलपूर्वक यौन संबंध बनाए जाने लगे। महिलाएं मुझे कॉल करती थीं और मुझे बताती थीं कि यदि हम सेक्स करने से मना कर देते हैं तो हमारे पति हमें पीटते हैं।"

-कोआर्डिनेटर

पार्टनर के हमेशा घर में साथ होने से ने महिलाओं के लिए सेक्स से इनकार करना कठिन बन गया था, क्योंकि इस इनकार के फलस्वरूप अक्सर हिंसा होती थी। अस्पतालों तक पहुँच न होने के कारण इस दौरान गर्भनिरोध के कुछ उपायों जैसे कि कॉपर-टी की उपलब्धता नहीं थी, गर्भनिरोध की केवल अस्थायी विधियां जैसे कि कंडोम ही उपलब्ध थे। हालांकि, आवाजाही और गतिशीलता पर प्रतिबंधों की वजह से ये विधियां भी पहुँच से बाहर हो गई थीं। संस्थाओं ने समुदायों में अनचाहे गर्भ के अधिक मामले पाए जाने के बारे में सूचित किया। इस दाव को मॉमजंक्शन जैसी संस्थाओं से भी बल मिलता है जिसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 40% तक अनियोजित गर्भावस्थाओं के कारण शिशुओं के जन्म में बढ़ोत्तरी पाई गई।[22]

> "अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं स्थगित हो गई थीं। जैसे कि यदि किसी को अनचाहा गर्भ हो जाए और वह गर्भपात कराना चाहे, तो अस्पताल बंद थे। तो फिर उनको नीम हकीमों का सहारा लेना पड़ता था और जड़ी बूटियां या दवाओं की दुकानों से गुप्त रूप से दवाएं लेनी पड़ती थीं जो उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली चीज़ें थीं। इसमें काफी धन भी खर्च होता था और बहुत कठिनाई से प्राणरक्षा हो पाती थी।"
>
> - फील्ड कार्यकर्ता

कुछ विशेष मामलों में, कोविड-19 के संपर्क में आने के भय के कारण पुरुषों ने अपनी पत्नियों को अस्पताल या आशा वर्करों के पास ले जाने से मना कर दिया। इस संदर्भ में, लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती को हिंसा के एक रूप में भी समझा जा सकता है।

जहाँ लॉकडाउन के शुरुआती महीनों के दौरान संस्थाएं हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता नहीं कर सकीं क्योंकि केवल इंटरनेट या फ़ोन से ही बातचीत करना संभव होता था, वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद उन्होंने एसजीबीवी के सूचित मामलों के संबंध में मोटे तौर पर दो विधियों का उपयोग किया।

22 पैनडेमिक फ्यूल्स बेबी बूम इन इंडिया, सेज लेटेस्ट रिपोर्ट बाय मॉमजंक्शन। दि इकोनॉमिक टाइम्स। (2020, दिसम्बर 20)। https://economictimes.indiatimes.com/industry/miscellaneous/pandemic-fuels-baby-boom-in-india-says-latest-report-by-momjunction/articleshow/80013971.cms?from=mdr.

पुरुषों के विरुद्ध एक्शन लेने और पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, पहला तरीका था। यह तरीका, पुरुषों को यह अहसास दिलाने पर आधारित था कि महिलाओं की सहायता और सपोर्ट के लिए एक कानूनी ढांचा मौजूद है। इसलिए, यदि महिला अपने पार्टनर को गिरफ्तार नहीं भी कराना चाहती थी, तो भी वह पुलिस अधिकारियों से अनुरोध कर सकती थी कि वे शोषणकर्ता को समझाएं और चेतावनी दें। दूसरा तरीका, पुरुषों की काउंसिलिंग करने और उनको यह समझाने पर केंद्रित था, कि हिंसा क्यों गलत है। यह तरीका, पुरुषों की दृष्टि में महिलाओं को इंसान समझकर उनसे मानवीयता का व्यवहार करने और यह बताने पर केंद्रित था कि कोविड-19 के कारण किस तरह से महिलाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संस्थाओं ने उनको समझाया कि पुरुषों और लड़कों को हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका उनके बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अलबत्ता ये दोनों ही तरीके महत्त्वपूर्ण थे, जो कुछ समय के लिए तुरंत समाधान करने पर केंद्रित थे।

इन मामलों में प्रतिक्रिया करने की कठिनाई यह इंगित करती है कि अनेक सिस्टम और प्रतिक्रिया प्रणालियां जो जीबीवी के लिए प्रोग्रामों द्वारा लागू की गई थीं, वे ऐसे अभूतपूर्व संकट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। साथ ही, जेंडर के मसले पर काम करने वाली कुछ संस्थाओं ने बताया कि उनके प्रोग्राम के प्रतिभागियों के घरों में हिंसा नहीं हो रही थी। क्रॉस-चेक करने के लिए इन संस्थाओं ने इन युवा पुरुषों के पार्टनरों और बच्चों से भी बात की, जिन्होंने भी इसकी पुष्टि की। ये युवा पुरुष अपने इलाके में अन्य पुरुषों और लड़कों की भी काउंसिलिंग कर रहे थे, ताकि समुदाय पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े।

जीबीवी के अलावा, सीमांत जातियों वाले समुदायों के विरुद्ध हिंसा के मामलों की भी रिपोर्ट की गई। इस प्रकार की हिंसा उच्च जाति वाले समुदायों द्वारा की जाती है और और अक्सर यथास्थिति को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था।

सीमांत जातियों वाले समुदायों के अस्वच्छ रहने से संबंधित जातिगत धारणाओं की वजह से, उनको अक्सर कोविड-19 का वाहक माना गया और यह तर्क उनके विरुद्ध भेदभाव को सही ठहराने के लिए प्रयोग किया गया। दलित, बहुजन और आदिवासी (डीबीए) समुदायों के विरुद्ध ऐसे जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के मामले राशन की दुकानों पर देखने को मिले, जहां उनसे अलग कतार में खड़े होने को कहा गया। एक अन्य उदाहरण में, पंचायत ने इन समुदायों के सदस्यों के साथ आपसी संपर्क से इनकार कर दिया।

> "राशन वितरण के दौरान, हमने देखा कि दो कतारें लगी थीं, जहां निम्न जातियों के लोग, उच्च जाति के लोगों से अलग कतार में खड़े थे। जब हमने इस बारे में पूछताछ की, तो हमें बताया गया कि लोगों की रहन-सहन की भिन्न दशाओं के कारण इस तरह का भेदभाव ज़रूरी है। पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने, जाति आधारित भेदभाव को इस तरह प्रोत्साहित किए जाने पर सवाल उठाया।"
>
> -कोऑर्डिनेटर

इसके अलावा, मीडिया द्वारा मुस्लिमों को खलनायक की तरह पेश करना [23] मुस्लिम समुदायों और फील्ड वर्करों के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी की एक वजह बना। एक संस्था ने बताया कि किस तरह से मुस्लिम बच्चों को गाँव के विशेष भागों में प्रवेश न करने के लिए चेतावनी दी गई या उन्होंने अपने नाम छिपाए क्योंकि उन्हें पकड़ लिए जाने का डर था। बच्चों से केवल उनके असली नाम छिपाने को कहा गया था, हालाँकि इसके पीछे की वजह उनको नहीं बताई गई। एक फील्ड कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि उनको अक्सर गाँवों में घुसने नहीं दिया जाता था और गाँव के लोगों के संपर्क से बचने के लिए अन्य वह रास्ता चुनते थे।

> "वास्तव में, मेरे साथ भेदभाव किया गया और मेरे नाम की वजह से मुझे अनेक गाँवों में जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं गांव के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए हमें अन्य रास्ता लेना होगा, क्योंकि हम दलितों के बीच काम कर रहे थे और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा था।"
>
> - फील्ड कार्यकर्ता

23 वेट्टिकाड ए. एम. (2020, मई 15)। इंडियन मीडिया, अक्यूज्ड ऑफ इस्लामोफोबिया फॉर इट्स कोरोनावायरस कवरेज। ब्रेकिंग न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ और अल जजीरा का वीडियो। https://www.aljazeera.com/news/2020/5/15/indian-media-accused-of-islamophobia-for-its-coronavirus-coverage

हमने क्या सर्वोत्तम किया...

I) हितधारकों को जोड़ना

कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि उत्तरदाता संस्थाओं के हितधारकों ने समुदायों की ज़रूरतें पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू कर दिया था। इंटरव्यू के दौरान हुई चर्चाओं में तीन मुख्य हितधारकों की पहचान की गई:

1. ग्राम प्रधान :

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं ने समुदायों के बीच आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर काम किया। एक संस्था ने सकारात्मक रोल मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए, अक्सर प्रधान की मौजूदगी में गाँव की बैठकों में पुरुषों के साथ काम करने की अपनी सफलता की कहानियाँ बताईं। एक अन्य संस्था ने प्रधानों के साथ मिलकर कार्य किया और उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता की ताकि वे शुरुआती लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभ पा सकें। प्रधानों के साथ मिलकर काम करने से यह सुनिश्चित हो गया की समुदाय अधिक व्यापक रूप से संस्थाओं को स्वीकार करेंगे।

2. स्थानीय प्रशासन और पुलिस:

प्रशासन के साथ मिलकर काम करने से संस्थाओं को बिना किसी परेशानी के सही ढंग से काम करने की सुविधा मिली। दो संस्थाओं ने, लॉकडाउन लागू होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध करके ई-पास प्राप्त किया ताकि उनके सदस्य एक से दूसरे स्थानों तक स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन कर सकें। परिणामस्वरूप, संस्थाओं का समुदायों से संपर्क हो सका और वे उनको राशन उपलब्ध करा पाए। दो संस्थाओं ने अपने ज़िलों में जन स्वास्थ्य की खराब स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, जिससे इस समस्या का सरकार द्वारा तेज़ी से समाधान किया गया। जेंडर के मसले पर काम करने वाली दो संस्थाओं ने पुलिस अधिकारियों को संवेदीकृत किया। अपने कार्य के अंतर्गत उन्होंने पुलिस अधिकारियों को तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान किए, ताकि वे घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करके सर्वाइवरों के हितों की रक्षा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों।

3. आशा कार्यकर्ता:

ग्रामीण उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के साथ सहभागिता ने सुनिश्चित किया की हर किसी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। आशा कार्यकर्ताओं ने एक गाँव से दूसरे गाँव जाकर हर ज़रूरतमंद को गर्भनिरोधक और पीपीई उपलब्ध कराई। जेंडर-संबंधित मामलों पर काम करने वाली संस्थाओं ने, गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक और पर्याप्त पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। इसके अलावा, जेंडर-संबंधित मुद्दों पर काम केंद्रित करने वाली एक संस्था ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे घरेलू हिंसा की स्थितियों में हस्तक्षेप करना जानते हों।

II) मिली-जुली चर्चाओं के आयोजन

1.आजीविका पर काम करने वाली संस्थाओं ने कोविड-19 संकट के कारण आई चुनौतियों का सामना करने के लिए, सुगमता आधारित चर्चाएं आयोजित कराते हुए उत्तर प्रदेश में श्रम अधिकारों में बदलावों के बारे में जागरूकता सृजन के जरिए प्रतिभागियों की पैरवी संबंधी क्षमताओं को मज़बूत बनाया। इससे प्रतिभागी, उस संदर्भ को अधिक सम्पूर्ण रूप में समझ सके, जिसमें वे स्वयं स्थित थे।

2. मर्दानगी पर काम करने वाली कुछ संस्थाओं ने अनलॉक के दौरान चर्चाओं और बैठकों के आयोजन करने के बारे में बताया, जिनमें उन्होंने युवा पुरुषों और लड़कों से आजीविकाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात की और उनके जीवन के इन अन्य पहलुओं पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में चिंतन करने के लिए माहौल दिया।

कोविड का एक वर्ष: आगे क्या करना है?

(I) विषय आधारित विस्तार

जल, स्वच्छता और शिक्षा की विषयों पर काम करने वाली संस्थाओं ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने विषय के फोकस और लक्ष्य समूहों में विविधीकरण की संभावनाओं में बढ़ोत्तरी के बारे में खासतौर से उल्लेख किया। इस संकट ने इन संस्थाओं को विविध विषयों के बीच आपसी संबंध बनाने और मज़बूत करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे अपने समुदायों पर कोविड-19 के बहुआयामी प्रभाव देख रही थीं, जिससे अधिक समग्र प्रतिक्रिया की ज़रूरत उठ खड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए, कोविड-19 संकट से पूर्व युवा पुरुषों और लड़कों के साथ जेंडर पर काम करने वाली एक संस्था ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा तक पहुँच मज़बूत बनाने की दिशा में कार्य करने के बारे में बताया, क्योंकि इस समय युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में शिक्षा पर विपरीत प्रभाव देखा गया था।

पूरे अध्ययन में यह देखा गया कि कोविड-19 संकट के दौरान, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने वाली संस्था, युवा पुरुषों और लड़कों के साथ अपने कार्य में एक मिला-जुला नज़रिया अपनाने की ज़रूरत के प्रति और अपनी विषय आधारित सहभागिताओं को विविधतापूर्ण बनाने की ज़रूरत को लेकर अधिक सजग रहे। उदाहरण के लिए, इन संस्थाओं ने अपने समुदायों में, किशोर लड़कों और लड़कियों के साथ मासिक चक्र संबंधी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भपात सहित यौन/सेक्सुअल और प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएच) के मसलों पर कार्य करने की ज़रूरत के बारे में सूचित किया और इस पर जोर दिया और आने वाले वर्षों में इस मसलों पर कार्य करने का अपना इरादा जाहिर किया।

इसी प्रकार से, जेंडर संबंधी मसलों पर काम करने वाली संस्थाओं ने मानसिक स्वास्थ्य और लॉकडाउन के दौरान समुदायों पर इसके विपरीत प्रभाव के संबंध में कार्य करने की ज़रूरत को समझा। हालाँकि, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान, दृष्टिकोण और तकनीकी कुशलताओं का अभाव, उनके लिए इस मसले पर कार्य या सहभागिता करना कठिन बनाता है। इस बीच, कोविड-19 संकट की पहली लहर के दौरान अपने कार्य में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने वाली संस्थाओं ने प्रायः समुदाय की तात्कालिक ज़रूरतों पर प्रतिक्रियाएं कीं, जैसे कि तनाव और दुश्चिंता से निपटना और भविष्य में ये कार्य करने के लिए किसी दीर्घकालीन निवेश या अपनी रुचि के बारे में सूचित नहीं किया।

कोविड-19 संकट की पहली लहर के दौरान अनचाही गर्भावस्थाओं में बढ़ोत्तरी ने स्वास्थ्य पर काम करने वाली संस्थाओं को मातृत्व स्वास्थ्य पर अपना फोकस बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जो एक विषय आधारित विषय के रूप में उभरा जिसके बारे में उनको महामारी के बाद भी लगातार कार्य करने की उम्मीद थी। जहां कोविड-19 के दौरान उभरते मसलों जैसे कि मातृत्व स्वास्थ्य को स्वास्थ्यसेवा पर काम करने वाली संस्थाओं की दीर्घकालीन योजनाओं में शामिल किया गया, वहीं इसके साथ उनकी दीर्घकालीन सहभागिता रणनीतियों में किसी बदलाव या विस्तार की योजना के बारे में नहीं सूचित किया गया। दूसरे शब्दों में, संस्थाओं द्वारा भविष्य में विषय आधारित फोकस में विविधता की संभावना जाहिर की गई, हालाँकि सहभागिता रणनीतियों के विविधीकरण के बारे में सीमित बातचीत ही की गई।

जेंडर-संबंधित मसलों पर कार्य करने वाली संस्थाओं ने कुछ सकारात्मक व्यवहारगत बदलावों का उल्लेख किया, जो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने प्रतिभागियों में देखे। उन्होंने बताया कि उनके प्रोग्राम के प्रतिभागी, महिलाओं की मासिक चक्र संबंधी ज़रूरतों के प्रति अधिक मददगार थे। मासिक चक्र संबंधी स्वास्थ्य के बारे में पहले सत्रों में भागीदारी करने के कारण, इनमें से अनेक पुरुष महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवा कर रहे थे। इसके विपरीत, स्वास्थ्य पर काम करने वाली संस्थाओं ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मासिक चक्र से संबंधित कलंक और मज़बूत बना और समुदायों में मासिक चक्र संबंधी स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव और गहरा हुआ। इससे इन संस्थाओं ने अपनी भावी प्रोग्राम योजनाओं में मासिक चक्र स्वच्छता और कलंक के संबंध में कार्य शामिल करने की ज़रूरत स्पष्ट की।

स्वास्थ्य और श्रम अधिकारों जैसी विषयों पर काम करने वाली अधिकांश संस्थाओं ने अपने प्रोग्रामों में अंतरालों की पहचान की, जो उनके विचार में अधिक मिले-जुले थे। इन योजनाओं में, एसआरएच, मासिक चक्र संबंधी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भपात के मसलों पर कार्य किया जाना शामिल था। उनकी कार्ययोजना में, युवाओं और सीमांत समुदायों के बीच अधिक कार्य किया जाना शामिल था, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच में सुधार किया जा सके। इससे संस्थाओं को आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा और जेंडर आदि मसलों के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिनके बारे में उनके विचार में फील्ड में चर्चा किए जाने की ज़रूरत है। हालाँकि, महामारी के बाद अपना दायरा और पहुँच बनाए रख पाना, उनके लिए एक चुनौती प्रतीत होती है।

(II) ऑनलाइन या ऑफलाइन?

यह उल्लेख किया जाना ज़रूरी है कि जहां अधिकांश संस्थाओं ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कार्य को ऑनलाइन शिफ्ट किए जाने की बात कही, वहीं सहभागिता की रणनीतियों में यह बदलाव अस्थायी माना गया। लगभग सभी संस्थाओं ने कहा कि भविष्य में, कोविड-19 संकट कम हो जाने के बाद, उनको उम्मीद है कि वे अपने संबंधित फील्ड और समुदायों में ऑफलाइन कार्य बहाल कर सकेंगे। संस्था, सहभागिता के ऑफलाइन मॉडल के पक्ष में प्रतीत हुए, जिसके बारे में उनका दावा कि इससे उनको प्रतिभागियों के शिक्षण, रुचि और सहभागिता की निगरानी के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। आगामी समय में कोविड-19 संकट की कई लहरों की संभावनाओं के बारे में महामारी विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मीडिया में व्यक्त अनुमानों को देखते हुए, न केवल एक अस्थायी उपाय के तौर पर, बल्कि यथासंभव प्रोग्रामों की दीर्घकालीन सहभागिता रणनीतियों के रूप में अधिक स्थायी ऑनलाइन सहभागिताएं विकसित करने की प्रबल ज़रूरत है।

(III) फंडिंग की समस्याएं

अध्ययन के लिए इंटरव्यू में शामिल छोटे पैमाने के संस्था, अपनी भावी योजनाओं को लेकर आमतौर से निराशावादी थे। केवल एक या दो जिलों में काम करने वाली संस्थाओं का मानना था कि एफसीआरए कानून, उनके प्रतिकूल है। जहां उनका मानना था कि एफसीआरए से उनको बैंक खाता खोलने और उसे

चलाने की सुविधा मिलेगी, वहीं उन्होंने यह भी महसूस किया कि भविष्य में उनके पास फंड अपेक्षाकृत कम हो जाएंगे। सीएसआर के नियमों में बदलावों ने उनकी फंडिंग को और भी कम किया है, इसलिए, इन संस्थाओं को केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कार्यरत रहने और अपना अस्तित्व बचाए रखने की उम्मीद है। अन्य संस्थाओं ने बताया कि उनको राशन वितरण के लिए फंड डाइवर्ट करने के लिए अपने प्रोग्राम संबंधी फंड्स में कटौती करनी पड़ी।

पर्याप्त फंड वाले, यूपी में कई लोकेशनों पर काम करने वाली संस्थाओं ने लंबे समय में अपने कार्य की नए सिरे से रणनीति बनाने और ऑनलाइन शिफ्ट करने की ज़रूरत मानी। परिवहन और गतिशीलता की चुनौतियों के बावजूद पहुँच में बढ़ोत्तरी, कोविड-19 संकट का एक सकारात्मक परिणाम मानी गई। इसलिए, कुछ संस्था अधिक स्थायी ऑनलाइन सहभागिताओं के लिए वेबसाइटें या फोन ऐप बनाने में निवेश की योजना बना रहे हैं, जो अधिक विविधतापूर्ण जनसंख्या के लिए अभिगम्य (पहुँच में) हों। यह उल्लेख करना रोचक है कि लंबे समय की ऑनलाइन सहभागिता रणनीतियां बनाने की क्षमता को लेकर संस्थाओं का आत्मविश्वास, ज़्यादा फंडिंग सपोर्ट और प्रोग्राम की अधिक बड़ी पहुंच के साथ जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

मिली-जुली प्रोग्रामिंग की दिशा में

इस अध्ययन के माध्यम से, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के लिए विविध विषयों पर आधारित विकास प्रोग्राम, कोविड-19 की पहली लहर और, इस संकट की प्रतिक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बाद में उठाए गए कदमों से विविध प्रकार से प्रभावित हुए। परिणामस्वरूप, इस अध्ययन के लिए इंटरव्यू में शामिल संस्थाओं ने अपने फंड खर्च कर के, अपनी सहभागिता और पहुंच की रणनीतियों में बदलाव करके और अपने विषय आधारित फोकस और लक्ष्य समूहों को विविधीकृत करते हुए अपने समुदायों को तुरंत राहत और सहायता प्रदान करने के अपने अनुभव साझा किए। साथ ही, संस्थाओं ने खासतौर से इस दौर में युवा पुरुषों और लड़कों के उभरते मसलों और सरोकारों के संदर्भ में अपने समुदायों पर कोविड-19 संकट के प्रभाव का भी उल्लेख किया। यह देखना रोचक है कि कोविड-19 संकट का युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन पर देखा गया प्रभाव, जिसके बारे में संस्थाओं ने बताया, वह उनके अपने विषय आधारित फोकस के क्षेत्र से परे था। जेंडर और मर्दानगी पर काम करने वाली संस्था, अपने प्रोग्रामों में शामिल युवा पुरुषों की आजीविका और रोजगार की संभावनाओं पर इस संकट के कारण पड़ने वाले प्रभाव और जेंडर संबंधी मसलों को लेकर उनकी सहभागिता पर इसके सहवर्ती प्रभाव को लेकर अधिक सजग दिखे। उदाहरण के लिए, संस्थाओं ने बताया कि आजीविकाओं के नुकसान के कारण युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में जेंडर - आधारित प्रोग्रामिंग की प्राथमिकता कम हो गई, क्योंकि वे अपने परिवारों के लिए आय और आर्थिक सहायता के नियमित स्रोत खोजने और बनाए रखने के दबाव से अधिक बोझिल होते जा रहे थे। इसी प्रकार से, आजीविका पर कार्य करने वाली संस्थाओं ने कोविड-19 संकट के कारण अपने प्रतिभागियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में सूचित किया, क्योंकि आजीविकाओं के नुकसान ने उनकी अपनी छवि को नकारात्मक प्रभावित किया था और शहरों से वापसी पलायन ने आय के नए स्रोत खोजने की संभावनाएं खोने का खतरा बढ़ा दिया था। साथ ही, संस्थाओं यह भी सूचित किया और देखा कि उनके प्रोग्रामों में शामिल विविध पहचान वाले प्रतिभागियों के कारण कोविड-19 संकट को उनके जीवन पर प्रभाव बहुत ही विविधतापूर्ण और अत्यधिक मिला-जुला था। इसलिए, प्रोग्रामिंग में आगे इस प्रभाव का समाधान करने के लिए, इन अवलोकनों को मिले-जुले नज़रिए के रूप में उपयोग करने की भरपूर संभावना है, जो न केवल पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और शिक्षाविधि को सूचित और विकसित करेगा, बल्कि प्रोग्राम की डिलीवरी को भी बेहतर बनाते हुए सेवाओं तक पहुँच मज़बूत बनाएगा। अध्ययन के निष्कर्षों से, विभिन्न विषयों को लेकर युवा पुरुषों और लड़कों के बीच कार्य करने वाली संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग मज़बूत बनाने की ज़रूरत भी सामने आती है। प्रोग्रामिंग का सहयोग आधारित तरीका यह सुनिश्चित कर सकेगा कि युवा पुरुषों और लड़कों विविधताओं को न केवल पहचाना जाए और पुष्टि की जाए, बल्कि उनका प्रभावी समाधान भी किया जाए। इसके अलावा, जैसा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर आधारित विषयों पर काम करने वाली संस्थाओं ने बताया, कि कोविड-19 संकट ने सभी विषयों में, युवा पुरुषों और लड़कों के बीच सभी विकास कार्यों में एक जेंडर रूपांतरणकारी नज़रिया शामिल करने की अभूतपूर्व ढंग से महत्त्वपूण ज़रूरत को रेखांकित किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संकट के समय जेंडर समानता और न्याय के सिद्धांतों को न केवल बनाए रखा जाए बल्कि एसआरएचआर, जीबीवी की रोकथाम और ईएफसीएम की रोकथाम के बारे में समुदायों में सकारात्मक सूचक उत्पन्न करते हुए इन प्रोग्रामों के प्रतिभागियों द्वारा और आगे बढ़ाया जाए।

जहां समुदायों पर कोविड-19 संकट के प्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन करने के लिए संस्थाओं के स्टाफ के इंटरव्यू लेकर इस अभ्यास द्वारा पर्याप्त डेटा एकत्रित किया गया, वहीं शहरी और ग्रामीण उत्तर प्रदेश में युवा पुरुषों और लड़कों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अन्य अध्ययन आयोजित करते हुए इस डेटा को संपूरित करने की आवश्यकता है। समुदायों के साथ सीधे आपसी संपर्क के माध्यम से साक्ष्य उत्पन्न करने का यह अभ्यास, युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन पर संकट और इसके प्रभाव के अनुभव का एक अधिक स्पष्ट और वास्तविक चित्रण प्रदान कर सकता है। युवा पुरुषों और लड़कों पर आयोजित प्रत्यक्ष अध्ययन, उनकी आजीविकाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य उभरती चिंताओं और उनके जीवन के मसलों पर विविध प्रभावों के अनुभवों से बंधी मर्दानगी की सोच पर भी कोविड-19 संकट के प्रभाव को समझने में सुगमता प्रदान कर सकता है। फलस्वरूप, इन विभिन्न मसलों पर युवा पुरुषों और लड़कों के साथ कार्यरत विकास प्रोग्रामों की सहभागिताओं में एक अधिक मिला-जुला और अखंड तरीका समावेशित किया जा सकता है, जो उनके जीवन पर और आत्म-छवि और मर्दानगी की सोच पर कोविड-19 के प्रभाव को लेकर गहराई से सचेत हो।

जहां कोविड-19 संकट के कारण युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन पर प्रभाव के बारे में आगामी रिसर्च, विकास प्रोग्रामों के लिए उनकी सहभागिताएं तद्नुसार अनुकूलित करने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा, वहीं वर्तमान अध्ययन में कोविड-19 संकट और संबंधित प्रभावों का सामना करने के लिए संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त वर्तमान सहभागिता रणनीतियों में एक चिंताजनक रुझान भी इंगित किया गया है। एक तो यह कि जहां अधिकांश संस्थाओं ने अपने सहभागिता के मॉडलों में ऑनलाइन प्लेटफार्मों की दिशा में बदलाव के बारे में सूचित किया, उन्होंने लॉकडाउन के समय यात्राओं और गतिशीलता पर प्रतिबंधों के परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव को एक अस्थायी उपाय के तौर पर ही देखा। प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के साथ, संस्थाओं ने फिर से अपने कार्य को जमीनी स्तर पर शुरू किया, अलबत्ता सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया गया और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रतिभागियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रखी गई और ऐसी उम्मीद की गई कि यह संकट का दौर गुजर जाने के साथ जमीनी स्तर पर कार्य कोविड-19 संकट से पहले की स्थितियों की तरह बहाल हो जाएगा। कोविड-19 संकट को लेकर मीडिया किए जा रहे अनेक लहरों के अनुमानों को देखते हुए, इस समय यह खासतौर से असंभावित प्रतीत होता है, जिसके साथ देश अभी 2021 में महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभावों की आशंकाओं से गुजर रहा है। इसलिए, जहां प्रोग्रामिंग को परिवेश में तात्कालिक बदलावों के लिए अनुकूलित किया गया है, वहीं ऐसे अधिक स्थायी प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाने की तत्काल ज़रूरत है जिनमें कोविड-19 जैसी आपदाओं के अधिक दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखा गया हो। हालाँकि यह सही है कि ऑनलाइन मॉडल, सीमांत समुदायों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में, पहुँच से संबंधित अनेक चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के प्रयास इस पहुँच में सुधार करने तथा इस दिशा में समुदायों की क्षमताएं बढ़ाने पर केंद्रित होने चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि प्रोग्राम, कोविड-19 संकट की भावी लहरों का सामना कर पाएंगे, बल्कि इससे संस्थाओं के लिए सुदूर क्रियान्वयन के सकारात्मक प्रभावों से जुड़ने की गुंजाइश भी बनेगी- उदाहरण के लिए, सहगणों (कोहार्ट) में ऐसे निःशक्त प्रतिभागियों को बड़ी संख्या में शामिल किया जाना, जिनके लिए यात्रा और गतिशीलता संबंधी प्रतिबंधों के कारण पहुँच के मसले, हमेशा ही एक समस्या रहे हैं। हालाँकि इसके लिए यह अपेक्षित है कि डिजिटल अंतराल, ड्रॉपआउट दरों में बढ़ोत्तरी, निगरानी और मूल्यांकन के टूल्स के वर्चुअल क्रियान्वयन और गैर-पाठ्यक्रम आधारित हस्तक्षेप कार्यक्रमों की डिलीवरी के कारण ऑनलाइन सहभागिता विकास में सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों पर संस्था प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनें। इसके अलावा, संकट के समय समुदायों की ज़रूरत के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन सहभागिताओं का मिला-जुला रूप विकसित करने में निवेश की दिशा में पूरे सेक्टर में संस्थाओं के लिए संवाद बनाए रखने ज़रूरी हैं, ताकि इस बारे में सामूहिक रूप से प्रोग्रामिंग और पैरवी के कार्यबिंदुओं (एक्शन प्वाइंट्स) को विकसित किया जा सके।

इसके अलावा, मिली-जुली विधियां अपनाना समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि परियोजनाओं का डिज़ाइन या सामाजिक प्रभाव कभी अलग-थलग नहीं होता, क्योंकि परियोजना के डिज़ाइन सांगठनिक मूल्यों और प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं, जबकि उनके प्रभाव, उस परियोजना के क्रियान्वयन वाले किसी समुदाय विशेष को संरचित करने वाली पहचानों की विविधता को प्रतिबिंबित करते हैं। अतएव, परियोजना के अलग-थलग होने से मौजूदा असमानताएं और बढ़ेंगी और विशेषकर संकट के समय समुदायों में उभरने वाले विशिष्ट और मिले-जुले सरोकारों और मसलों को समग्रता के साथ समझने में बाधा आएगी। जैसा कि अध्ययन के निष्कर्षों से जाहिर है, युवा पुरुषों और लड़कों पर कोविड-19 संकट का प्रभाव, इन प्रतिभागियों की विविध पहचानों, जैसे कि जाति, के आधार पर भी विविधतापूर्ण रहा। उदाहरण के लिए, सीमांत जाति वाले समुदायों में युवा पुरुषों और लड़कों पर काम करने वाली कुछ संस्थाओं ने, लॉकडाउन के दौरान और उसके पश्चात, जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा के अनुभवों के अनुसार नौकरी के अवसरों तथा सामाजिक स्थायित्व और दर्जे पर कोविड-19 संकट के विपरीत प्रभाव का खासतौर से उल्लेख किया। वर्ग और धर्म आधारित अन्य पहचान सूचकों के बारे में भी संस्थाओं द्वारा इसी तरह के अवलोकन सूचित किए गए। विविध पहचानों पर आधारित प्रभाव की यह विशिष्टता, विभिन्न मसलों पर उनके साथ काम करने वाली संस्थाओं की ओर से ध्यान केंद्रित किए जाने की माँग करती है। युवा पुरुषों और लड़कों पर इस परिवर्तनीय प्रभाव का समाधान करने के लिए औरत और मर्द के जेंडर विभाजन से आगे बढ़ना और इन श्रेणियों में विभिन्न सामाजिक पहचानों के बीच मिले-जुले स्वरूपों पर फोकस करना तथा यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि युवा पुरुष और लड़के, एकसमान श्रेणी नहीं होते और यह कि वे भिन्न हैं तथा उनमें भी पदानुक्रम मौजूद हैं। उनमें से सर्वाधिक सीमांत लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना, भविष्य के लिए बेहतर विकास की कुंजी हो सकती है। इसके अलावा, संकट के समय उजागर होने वाली अनेक असमानताएं, जैसे कि शिक्षा, आजीविकाओं तक पहुँच, जेंडर - आधारित हिंसा में बढ़ोत्तरी, आदि जो मर्दानगी के परिप्रेक्ष्य में समझी जाती हैं, वे इन विविध पहचान वाली लोकेशनों से अत्यधिक संबंधित हैं और इसलिए मर्दानगी की मिली-जुली धारणा वाले नज़रिए से प्रोग्रामिंग, इनको अधिक बेहतर समझने और अधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो सकेगी।

बेहतर पुनर्विकास (बिल्डिंग बैक बेटर)

अब जबकि हम कोविड-19 संकट की भावी लहरों को लेकर या कोरोना वायरस के नए वैरिएंट्स द्वारा संभावित भावी तबाही से आशंकित हैं, तो ये संभावनाएं, कमियां दूर करने और मानवीय सहायता और विकास के प्रयासों के बीच बेहतर संबंध निर्मित करने के लिए आगामी चर्चाओं और अध्ययन को तथा मौजूदा विकास प्रोग्रामों और इन प्रोग्रामों से सहभागिता वाले समुदायों की सहनशीलता की क्षमताएं निर्मित करने के लिए निवेश को अनिवार्य बना देती हैं। इस अध्ययन रिपोर्ट में, कोविड-19 संकट की पहली लहर को पार करने की हमारी सामूहिक संस्थागत यादें सहेजने में योगदान करने का तथा भावी अध्ययन, राहत और पुनर्विकास के भावी प्रयासों हेतु सहयोग करने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ सूची

ब्रेसेड। (2016, जनवरी)। जेंडर एंड रिसाइलेंस: फ्रॉम थ्यौरी टू प्रैक्टिस। रिलीफवेब-इन्फॉर्मिंग ह्यूमैनिटेरियन्स वर्ल्डवाइड।
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10224.pdf

चौरसिया, एम. , एवं पीटरसन, एच. ई. (2020, जुलाई 1)। इंडियारैक्ड बाय दि ग्रेटेस्ट एक्सडस सिंस पार्टिशन ड्यू टू कोरोनावायरस । दि गार्जियन।
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/india-wracked-by-greatest-exodus-since-partition-due-to-coronavirus

डेलोइट। (2020, अक्टूबर)। सोशल रिस्पांस टू कोविड-19: रोडमैप टू रिकवरी थ्रू डेवेलपमेंट एंड सीएसआर इनीशिएटिव्स।
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-about-deloitte-covid-19-response-document-indias-development-sector-noexp.pdf

डेवेलपमेंट सेक्टर : एडॉप्टिंग टू दि न्यू इकोसिस्टम इन दि कोविड-19 एरा। (2021, मार्च)। वी कम्युनिकेशन।
https://we-worldwide-arhxo0vh6d1oh9i0c.stackpathdns.com/media/450023/avian-we-social-impact-whitepaper_digital_03152021.pdf

एक साथ अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ, संगठनों का समूह है जो वयस्क पुरुषों और लड़कों के साथ कार्य करते हुए जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं।
https://www.eksaathcampaign.net/

एक्सप्रेस न्यूज सर्विस। (2021, जनवरी 7)। ऑफ्टर कोविड, केसेज ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट स्पाइक्ड बाय 5 टाइम्स। दि इंडियन एक्सप्रेस।
https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/after-covid-cases-of-online-harassment-spiked-by-5-times-7137386/

IFPRI. (2014, September). Resilience programming among non-governmental organizations: Lessons for policymakers.
https://www.ifpri.org/file/34511/download

इनानी आर. (2021, जनवरी 22)। इंडिया'ज पुअर आर ईटिंग इनटू देयर सेविंग्स, थैंक्स टु हाई इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 इंडियास्पेंड: डेटा जर्नलिज्म, एनालिसिस ऑन इंडियन इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थकेयर,एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स ।
https://www.indiaspend.com/economy/indias-poor-are-eating-into-their-savings-thanks-to-high-inflation-covid-19-716956

इन्फार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश (2020) '6/7 press note.pdf-Google Drive' अवैलेबल एट:
https://drive.google.com/file/d/1cwpaqzYaWBt_I_7U2rusRJ0qZZ8yQiDe/view

कलिता के.के. (2020, जुलाई 16)। पुलिस ब्रूटैलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन एंड इंडियन मेजॉरिटी क्लासेज। नार्थईस्ट नाउ।
https://nenow.in/opinion/police-brutality-against-vulnerable-and-indian-majority-classes.html

मंदर, एच. (2021)। लॉकिंग डाउन दि पूअर (2021 ed.)। स्पीकिंग टाइगर बुक्स।

मिंट। (2020, अगस्त 21)। मिलियंस एस्केप्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोविड-19 ब्रॉट इट बैक। .
https://www.livemint.com/news/india/millions-escaped-caste-discrimination-covid-19-brought-it-back-11597974483827.html

पैनडेमिक फ्यूल्स बेबी बूम इन इंडिया, सेज लेटेस्ट रिपोर्ट बाय मॉमजंक्शन । दि इकोनॉमिक टाइम्स। (2020, दिसम्बर 20)।
https://economictimes.indiatimes.com/industry/miscellaneous/pandemic-fuels-baby-boom-in-india-says-latest-report-by-momjunction/articleshow/80013971.cms?from=mdr

पांडे, के. (2020, जुलाई 30)। कोविड-19 लॉकडाउन हाइलाइट्स इंडियाज ग्रेट डिजिटल डिवाइड। डाउन टू अर्थ।
https://www.downtoearth.org.in/news/governance/covid-19-lockdown-highlights-india-s-great-digital-divide-72514

पीटीआई। (2020, नवम्बर 19)। इंडियाज ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन दि हेल्थ सेक्टर लो, सेज नीति आयोग मेम्बर। दि हिंदू।
https://www.thehindu.com/news/national/indias-overall-spending-on-health-sector-low-says-niti-aayog-member/article33132569.ece

रवि आर. सी. (2020) लॉकडाउन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ड्यू टू कोविड-19: एनी इंपैक्ट ऑन दि एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया? जर्नलिज्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोमोशन, 9, 209।
https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_327_20

सोनवाने, एस. (2020, दिसम्बर 1)। दि जेंडर्ड इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्कूल एजुकेशन। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी।
https://www.cbgaindia.org/blog/gendered-impact-covid-19-school-education/

दि एसेंसियल्स फॉर रिस्पांडिंग टू वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एंड ऑफ्टर कोविड-19। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी (आईआरसी)। (2020, जून 29)।
https://www.rescue.org/report/essentials-responding-violence-against-women-and-girls-during-and-after-covid-19.

वाईपी फाउंडेशन। (2019)। मर्दों वाली बातें:
ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेन मस्क्युलिनिटीज एंड एसआरएचआर ।

वाईपी फाउंडेशन। (2020)। यूथ इनसाइट : इनफार्मिंग कोविड-19 रिलीफ एंड रिस्पांस विद यंग पीपुल्स एक्सपीरियंसेज।

टीएन: एट लीस्ट 30 मेज़र इंसिडेंट्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड वायलेंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, सेज स्टडी। (2020, सितम्बर 18)। न्यूजक्लिक।
https://www.newsclick.in/Tamil-Nadu-Caste-Based-Violence-COVID-19-Lockdown

यूएन वीमेन। (2020)। कोविड-19 एंड एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स।
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

वेट्टिकाड ए. एम. (2020, मई 15)। इंडियन मीडिया, अक्यूज्ड ऑफ इस्लामोफोबिया फॉर इट्स कोरोनावायरस कवरेज। ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड न्यूज और अल जजीरा का वीडियो।
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/15/indian-media-accused-of-islamophobia-for-its-coronavirus-coverage

परिशिष्ट

I. युवा पुरुषों और लड़कों पर कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी का असर प्रवास/ बेरोज़गारी/ पोषण/ स्वास्थ्य/शिक्षा पर कार्य कर रहे संस्थाओं के लिए इंटरव्यू प्रश्नावली।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
इतिहास और बैकग्राउंड (कोविड-19 (COVID-19) से पहले) (20 मिनट)		
1. आप इस संस्था में कितने समय से काम कर रहे हैं? इस काम की किस बात ने आपमें इसे करने की रुचि जगाई?	प्रतिभागी के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, और फील्ड में उसके कार्य के बारे में गहरी जानकारी पाने के लिए भी।	
2. क्या आप अपने संस्था के काम के इतिहास और बैकग्राउंड के बारे में और इस समय वह जिस काम में लगा है उस काम के बारे में बता सकते हैं?	i) किसी समुदाय विशेष में संस्था के इतिहास और बैकग्राउंड को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए। ii) संस्था जिन प्रतिभागियों के साथ काम करता है उनकी पहचान की बनावट को समझने के लिए। iii) कोविड-19 (COVID-19) से पहले के संदर्भ में समुदाय की ज़रूरतों को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	**संकेत:** -आप किस चीज़ पर काम करते हैं? -इसे करते हुए आपको कितने साल हो गए हैं? -आप जिन प्रतिभागियों के साथ काम करते हैं उनका विवरण क्या है? (लिंग, आयु वर्ग, जाति, धर्म, वर्ग, स्थान) -उस समय आपने यह काम क्यों शुरू किया था?
3. क्या आप उन थीम्स (विषयों) और कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं जिनमें आपके संस्था ने कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप से पहले अपने काम में युवा पुरुषों और लड़कों को लगाया/शामिल किया था?	संस्था के थीम्स (विषयों) को मापने के लिए।	यदि आपका मानना है कि पिछले प्रश्नों में इसका उत्तर दिया जा चुका है, तो आप यह प्रश्न छोड़ सकते हैं।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
4. आपका संस्था समुदाय के साथ किस प्रकार व्यवहार करते/उनके साथ संलग्न होते हैं और इसके लिए आप किन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं? कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी से पहले इन संलग्नताओं की बारंबारता क्या थी?	संलग्नता की प्रकृति और प्रक्रियाओं को समझने के लिए।	संकेत: पुरुषों को किस रूप में संलग्न किया जाता है, समुदाय के नेताओं के रूप में, लोगों को जुटाने वालों के रूप में, या प्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में? वर्कशॉप, सामुदायिक कार्य, समूह गठन, कौशल निर्माण आदि।
5. आपका संस्था अपने कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को कैसे जुटाता है?	समुदाय के साथ संलग्नता की प्रक्रिया को समझने के लिए।	
6. आपके कार्य की पहुंच और पैमाना क्या है?	कोविड-19 (COVID-19) से पहले की पहुंच को मापने के लिए।	
कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी का असर		
7. क्या आप कृपा करके अपने कार्यक्रम और कार्य पर कोविड-19 (COVID-19) के असर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? • आप जिस प्रकार के कार्य में संलग्न होते हैं क्या उस प्रकार के मामले में फोकस में कोई बदलाव हुआ है? (थीमेटिक (विषयक) बदलाव) • क्या आपके कार्यक्रम की पहुंच और पैमाने में कोई बदलाव आया है? • कार्य की वे मुख्य गतिविधियां/क्षेत्र कौन-से हैं जिन पर कोविड-19 (COVID-19) संकट का कोई असर नहीं हुआ है और वे अभी-भी जारी हैं?	कार्यक्रम के कार्यान्वयन और डिज़ाइन पर पड़े असर को मापने के लिए।	**संकेत**: क्या आपको अपने कार्यक्रम की डिज़ाइन में या उसके कार्यान्वयन में कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के कारण कोई बदलाव दिखा है? क्या कार्यक्रम की समय-सीमाओं पर कोई असर हुआ है? क्या असर हुआ है? और आपने इस असर के साथ खुद को कैसे ढाला है?

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
8. आपके संस्था/कार्यक्रम ने वैश्विक-महामारी के हर चरण में सामने आने वाली अलग-अलग ज़रूरतों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी है? • क्या आप याद करके बता सकते हैं कि कब-कब क्या-क्या हुआ था? • क्या आपके संस्था ने इस अवधि में युवा पुरुषों और लड़कों के साथ कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित किसी कार्य की शुरुआत की थी? • आपके संस्था ने उनकी कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित ज़रूरतों की पहचान कैसे की?	कोविड-19 (COVID-19) ने फील्ड पर जो परिवर्तनशील असर डाला उस पर संस्था की प्रतिक्रिया को मापने के लिए।	
घटाव के तरीके (10 मिनट)		
9. आपके काम पर वैश्विक-महामारी का जो असर पड़ा है उसके कारण उस समय पैदा होने वाली चुनौतियों के प्रति आपके संस्था ने खुद को किस तरह ढाला है? • क्या संस्था संलग्नता की नई विधियां या मॉडल ढाल पाया? • क्या ऐसे कोई तरीके थे जिन्होंने आपके संस्था के लिए अच्छी तरह काम किया?	घटाव के सफल तरीकों, खुद को ढालने के मॉडलों/विधियों को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	यह उपयोगी रहेगा कि पिछले प्रश्नों में उन्होंने अपने कार्य की राह में कोविड (COVID) के कारण आईं जिन चुनौतियों या कार्य पर पड़े जिन असर के बारे में बताया है उसकी एक सूची बना लें और फिर एक-एक करके उनके बताए हर असर के लिए उनसे उसका सामना करने या खुद को ढालने के तरीकों के बारे में पूछें। यहां विशिष्ट रूप से पूछताछ करना उपयोगी रहेगा। क्या ऐसा कोई कारण था जिसके चलते उन तरीकों ने आपके संस्था के लिए कार्य किया/नहीं किया? संकेत - फंडिंग संबंधी चिंताएं और तरीकों की रचना।
10. क्या कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी और उसके बाद लगे लॉकडाउन के कारण आपके कार्य के नतीजों तक पहुंचने की राह में कोई खास चुनौतियां आई हैं?	पुरुषों के साथ कार्य करते समय नतीजों तक पहुंचने की राह की चुनौतियों को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
क्या इन कुछ महीनों में आपने और कुछ ऐसा देखा या अनुभव किया जिसे आप हमें बताना चाहते हों?	प्रतिभागी को विषय से संबंधित कोई भी अन्य किस्सा, अनुभव, चुनौती या ऐसी चीज़ें जो उसने नोट की हों, उन्हें हमें बताने का मौका देते हुए बातचीत खत्म करने के लिए।	संकेत: नई सीख, इस समय जारी चुनौतियों आदि से संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ जो वे हमें बताना चाहते हों।

II. युवा पुरुषों और लड़कों पर कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी का असर लिंग और मर्दानगी पर कार्य कर रहे संस्थाओं के लिए इंटरव्यू प्रश्नावली।)

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
इतिहास और बैकग्राउंड (कोविड-19 (COVID-19) से पहले) (20 मिनट)		
1. आप इस संस्था में कितने समय से काम कर रहे हैं? इस काम की किस बात ने आपमें इसे करने की रुचि जगाई?	प्रतिभागी के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, और फील्ड में उसके कार्य के बारे में गहरी जानकारी पाने के लिए भी।	
2. क्या आप अपने संस्था के काम के इतिहास और बैकग्राउंड के बारे में और इस समय वह जिस काम में लगा है उस काम के बारे में बता सकते हैं?	i) संस्था के कार्य के इतिहास और बैकग्राउंड को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए। ii) यह कार्य जिन युवा लड़कों और पुरुषों के साथ संलग्न होता है उनकी पहचान की बनावट को समझने के लिए। iii) कोविड-19 (COVID-19) से पहले के संदर्भ में युवा पुरुषों और लड़कों की ज़रूरतों को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	संकेत: -आप किस चीज़ पर काम करते हैं? -इसे करते हुए आपको कितने साल हो गए हैं? -आप जिन प्रतिभागियों के साथ काम करते हैं उनका विवरण क्या है? (लिंग, आयु वर्ग, जाति, धर्म, वर्ग, स्थान) -उस समय आपने यह काम क्यों शुरू किया था?
3. क्या आप उन थीम्स (विषयों) और कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं जिनमें आपके संस्था ने कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप से पहले अपने काम में युवा पुरुषों और लड़कों को लगाया/शामिल किया था?	संस्था के थीम्स (विषयों) को मापने के लिए।	यदि आपका मानना है कि पिछले प्रश्नों में इसका उत्तर दिया जा चुका है, तो आप यह प्रश्न छोड़ सकते हैं। यहां हम आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, और WASH (जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य-रक्षा) के संदर्भ में मर्दानगी कार्यक्रम के संबंध को समझने की कोशिश कर सकते हैं

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
4. आपका संस्था समुदाय के साथ किस प्रकार व्यवहार करते/उनके साथ संलग्न होते हैं और इसके लिए आप किन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं? कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी से पहले इन संलग्नताओं की बारंबारता क्या थी?	संलग्नता की प्रकृति और प्रक्रियाओं को समझने के लिए।	**संकेत**: पुरुषों को किस रूप में संलग्न किया जाता है, समुदाय के नेताओं के रूप में, लोगों को जुटाने वालों के रूप में, या प्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में? वर्कशॉप, सामुदायिक कार्य, समूह गठन, कौशल निर्माण आदि।
5. आपका संस्था अपने कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को कैसे जुटाता है?	चूंकि लोगों को जुटाना मर्दानगी कार्यक्रम में एक बड़ा मुद्दा रहा है। और बाद में कोविड (COVID) के संदर्भ में इसकी तुलना करना उपयुक्त होगा।	
6. आपके संस्था के कार्य की पहुंच और पैमाना क्या है?	कोविड-19 (COVID-19) से पहले की पहुंच को मापने के लिए।	
कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी का असर (15-17 मिनट))		
7. क्या आप कृपा करके अपने कार्यक्रम और कार्य पर कोविड-19 (COVID-19) के असर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? • आपका संस्था जिस प्रकार के कार्य में संलग्न होते हैं क्या उस प्रकार के मामले में फोकस में कोई बदलाव हुआ है? (थीमेटिक (विषयक) बदलाव) • क्या आपके कार्यक्रम की पहुंच और पैमाने में कोई बदलाव आया है? • कार्य की वे मुख्य गतिविधियां/क्षेत्र कौन-से हैं जिन पर कोविड-19 (COVID-19) संकट का कोई असर नहीं हुआ है और वे अभी-भी जारी हैं?	कार्यक्रम के कार्यान्वयन और डिज़ाइन पर पड़े असर को मापने के लिए।	**संकेत**: क्या आपको अपने कार्यक्रम की डिज़ाइन में या उसके कार्यान्वयन में कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के कारण कोई बदलाव दिखा है? क्या कार्यक्रम की समय-सीमाओं पर कोई असर हुआ है? क्या असर हुआ है? और आपने इस असर के साथ खुद को कैसे ढाला है?

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
8. आपके संस्था/कार्यक्रम ने वैश्विक-महामारी के हर चरण में सामने आने वाली अलग-अलग ज़रूरतों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दी है? • क्या आप याद करके बता सकते हैं कि कब-कब क्या-क्या हुआ था? • क्या आपके संस्था ने इस अवधि में युवा पुरुषों और लड़कों के साथ कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित किसी कार्य की शुरुआत की थी? • आपके संस्था ने उनकी कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित ज़रूरतों की पहचान कैसे की?	कोविड-19 (COVID-19) ने फील्ड पर जो परिवर्तनशील असर डाला उस पर संस्था की प्रतिक्रिया को मापने के लिए।	
घटाव के तरीके (10 मिनट)		
9. आपके काम पर वैश्विक-महामारी का जो असर पड़ा है उसके कारण उस समय पैदा होने वाली चुनौतियों के प्रति आपके संस्था ने खुद को किस तरह ढाला है? • क्या संस्था संलग्नता की नई विधियां या मॉडल ढाल पाया? • क्या ऐसे कोई तरीके थे जिन्होंने आपके संस्था के लिए अच्छी तरह काम किया?	घटाव के सफल तरीकों, खुद को ढालने के मॉडलों/विधियों को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	यह उपयोगी रहेगा कि पिछले प्रश्नों में उन्होंने अपने कार्य की राह में कोविड (COVID) के कारण आईं जिन चुनौतियों या कार्य पर पड़े जिन असर के बारे में बताया है उसकी एक सूची बना लें और फिर एक-एक करके उनके बताए हर असर के लिए उनसे उसका सामना करने या खुद को ढालने के तरीकों के बारे में पूछें। यहां विशिष्ट रूप से पूछताछ करना उपयोगी रहेगा। क्या ऐसा कोई कारण था जिसके चलते उन तरीकों ने आपके संस्था के लिए कार्य किया/नहीं किया?
10. क्या कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी और उसके बाद लगे लॉकडाउन के कारण आपके कार्य के नतीजों तक पहुंचने की राह में कोई खास चुनौतियां आई हैं?	पुरुषों के साथ कार्य करते समय नतीजों तक पहुंचने की राह की चुनौतियों को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	संकेत - फंडिंग संबंधी चिंताएं और तरीकों की रचना।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
क्या इन कुछ महीनों में आपने और कुछ ऐसा देखा या अनुभव किया जिसे आप हमें बताना चाहते हों?	प्रतिभागी को विषय से संबंधित कोई भी अन्य किस्सा, अनुभव, चुनौती, जो उसने नोट की हों, उन्हें हमें बताने का मौका देते हुए बातचीत खत्म करने के लिए।	संकेत: नई सीख, इस समय जारी चुनौतियों आदि से संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ जो वे हमें बताना चाहते हों।

III. युवा पुरुषों और लड़कों पर कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी का असर प्रवास/ बेरोज़गारी/ पोषण/ स्वास्थ्य/शिक्षा पर कार्य कर रहे फील्डकर्मियों के लिए इंटरव्यू प्रश्नावली।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
परिचय		
1. आप इस संस्था में कितने समय से काम कर रहे हैं? इस काम की किस बात ने आपमें इसे करने की रुचि जगाई?	प्रतिभागी के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, और फील्ड में उसके कार्य के बारे में गहरी जानकारी पाने के लिए भी।	
2. आपका संस्था किन-किन स्थानों पर काम करता है?	प्रतिभागी के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, और फील्ड में उसके कार्य के बारे में गहरी जानकारी पाने के लिए भी।	
3. आपका संस्था किन समुदायों में काम करता है?	प्रतिभागी जिन समुदायों में काम करता है उन समुदायों की पहचान की बनावट को समझने के लिए।	**संकेत**: लिंग, आयु वर्ग, जाति, धर्म, वर्ग, स्थान पर आधारित पहचान।
4. क्या आपका संस्था पिछले लगभग पूरे साल से इन्हीं स्थानों में और इन्हीं समुदायों में काम करता आ रहा है?	कोविड-19 (COVID-19) के संकट के कारण संपर्क या पहुंच-विस्तार में जो भी संभावित बाधाएं आई हों या बदलाव हुए हों उन्हें मापने और उनका लेखा-जोखा देने के लिए।	
5. क्या आप अपनी भूमिका और उन गतिविधियों व कार्यों के बारे में थोड़ा-बहुत बता सकते हैं जो आमतौर पर आप करते हैं?	प्रतिभागी जो काम करता है उसकी प्रकृति को समझने के लिए।	यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन प्रश्नों के दायरे की समझ हासिल हो सकती है जिनके उत्तर प्रतिभागी संभवतः दे पाएगा।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी का असर		
6. कोविड-19 (COVID-19) और उसके बाद पूरे देश में जो लॉकडाउन लगा उससे आपको उन समुदायों पर क्या असर दिखा जिनके साथ आपका संस्था काम करता है?	समुदायों पर पड़े असर को मापने के लिए, ताकि एक व्यापक संदर्भ तैयार हो सके जिसमें युवा पुरुषों और लड़कों को रख कर देखा जा सके।	
7. क्या आपके संस्था ने युवा पुरुषों और लड़कों पर वैश्विक-महामारी और लॉकडाउन का कोई खास या अलग असर देखा है? • कोविड-19 (COVID-19) और इसे संभालने के लिए किए गए उपायों के कारण युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में कौन-से बदलाव आए हैं? (3-4 बदलाव) • घरेलू काम के संबंध में पुरुषों और लड़कों की लॉकडाउन पर क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या वे काम में हाथ बंटा रहे हैं, या नहीं? • क्या आपके संस्था को समुदाय में हिंसा से जुड़े कोई बदलाव दिखे या नई समस्याएं दिखीं? पुरुषों के विरुद्ध हिंसा, या पुरुषों द्वारा हिंसा? • आप जिन समुदायों के साथ काम करते हैं, क्या उनमें लॉकडाउन में जीबीवी (लिंग-आधारित हिंसा) बढ़ गई थी? • क्या इस वैश्विक-महामारी ने युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में कोई अन्य उभरती हुई चिंता/समस्या/बेचैनी को जन्म दिया है?	जिनसे प्रतिभागी की बातचीत हुई हो उन युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन पर कोविड-19 (COVID-19) संकट और लॉकडाउन द्वारा पड़े असर को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए। चूंकि हो सकता है कि प्रतिभागी, मर्दानगी और लिंग से जुड़े सीधे प्रश्नों के उत्तर न दे पाए, अतः घरेलू काम और हिंसा से जुड़े इन प्रश्नों के लिए थोड़ी खोजबीन की ज़रूरत हो सकती है और यह खोजबीन मर्दानगी की धारणाओं पर पड़े असर को दस्तावेज़ी रूप देने में मददगार होगी।	
8. क्या युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में हुए इनमें से किसी भी उभरते हुए बदलाव ने आपके काम पर उनकी प्रतिक्रिया/लगन पर असर डाला है?	अन्य समस्याओं के बारे में युवा पुरुषों और लड़कों के साथ किए जाने वाले विकास-संबंधी कार्य में लैंगिक दृष्टि के उपयोग के दायरे को मापने के लिए।	

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
• क्या इससे आपके कार्यक्रम के नतीजों पर असर पड़ा है? क्या इन कुछ महीनों में आपने और कुछ ऐसा देखा या अनुभव किया जिसे आप हमें बताना चाहते हों?	प्रतिभागी को विषय से संबंधित कोई भी अन्य किस्सा, अनुभव, चुनौती या ऐसी चीज़ें जो उसने नोट की हों, उन्हें हमें बताने का मौका देते हुए बातचीत खत्म करने के लिए।	**संकेत**: नई सीख, इस समय जारी चुनौतियों आदि से संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ जो वे हमें बताना चाहते हों।

IV. युवा पुरुषों और लड़कों पर कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी का असर लिंग और मर्दानगी पर कार्य कर रहे फील्डकर्मियों के लिए इंटरव्यू प्रश्नावली।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
परिचय		
1. आप इस संस्था में कितने समय से काम कर रहे हैं? इस काम की किस बात ने आपमें इसे करने की रुचि जगाई?	प्रतिभागी के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, और फील्ड में उसके कार्य के बारे में गहरी जानकारी पाने के लिए भी।	
2. आपका संस्था किन-किन स्थानों पर काम करता है?	प्रतिभागी के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए, और फील्ड में उसके कार्य के बारे में गहरी जानकारी पाने के लिए भी।	
3. आपका संस्था किन समुदायों में काम करता है?	प्रतिभागी जिन समुदायों में काम करता है उन समुदायों की पहचान की बनावट को समझने के लिए।	**संकेत**: लिंग, आयु वर्ग, जाति, धर्म, वर्ग, स्थान पर आधारित पहचान।
4. क्या आपका संस्था पिछले लगभग पूरे साल से इन्हीं स्थानों में और इन्हीं समुदायों में काम करता आ रहा है?	कोविड-19 (COVID-19) के संकट के कारण संपर्क या पहुंच-विस्तार में जो भी संभावित बाधाएं आई हों या बदलाव हुए हों उन्हें मापने और उनका लेखा-जोखा देने के लिए।	
5. क्या आप अपनी भूमिका और उन गतिविधियों व कार्यों के बारे में थोड़ा-बहुत बता सकते हैं जो आमतौर पर आप करते हैं?	प्रतिभागी जो काम करता है उसकी प्रकृति को समझने के लिए।	यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन प्रश्नों के दायरे की समझ हासिल हो सकती है जिनके उत्तर प्रतिभागी संभवतः दे पाएगा।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी का असर		
6. कोविड-19 (COVID-19) और उसके बाद पूरे देश में जो लॉकडाउन लगा उससे आपको उन समुदायों पर क्या असर दिखा जिनके साथ आपका संस्था काम करता है?	समुदायों पर पड़े असर को मापने के लिए, ताकि एक व्यापक संदर्भ तैयार हो सके जिसमें युवा पुरुषों और लड़कों को रख कर देखा जा सके।	
7. क्या आपके संस्था ने युवा पुरुषों और लड़कों पर वैश्विक-महामारी और लॉकडाउन का कोई खास या अलग असर देखा है? • कोविड-19 (COVID-19) और इसे संभालने के लिए किए गए उपायों के कारण युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में कौन-से बदलाव आए हैं? (3-4 बदलाव) • क्या इसने समुदाय के अन्य लोगों/परिजनों के साथ उनके संबंधों पर असर डाला है? किस तरह से? • क्या आपके संस्था ने उनमें से किसी को खुद को एक मर्द के रूप में देखने के उसके तरीके के बारे में, या इस संदर्भ में मर्दानगी के बारे में बात करते सुना है? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि वे बातें क्या थीं? - आप जिन युवा पुरुषों और लड़कों के साथ संलग्न होते हैं क्या उनके जीवन में व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों में कोई बदलाव हुआ है? - क्या मर्दानगी को लेकर उनकी जो समझ है उसमें कोई बदलाव/तबदीली हुई है?	जिनसे प्रतिभागी की बातचीत हुई हो उन युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन पर कोविड-19 (COVID-19) संकट और लॉकडाउन द्वारा पड़े असर को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए। यह मापने के लिए क्या प्रतिभागी ने समुदाय के लोगों के बीच के संबंधों में ऐसे कोई बदलाव नोट किए हैं जो युवा पुरुषों और लड़कों की मर्दानगी की समझ में हुए बदलाव का नतीजा हों या जिनके कारण युवा पुरुषों और लड़कों की मर्दानगी की समझ में बदलाव आ सकते हों। चूंकि इस प्रतिभागी ने मर्दानगी और लिंग के विषय पर युवा पुरुषों और लड़कों के साथ कार्य किया होगा, अतः यह प्रतिभागी मर्दानगी की समझ में हुए बदलावों, लैंगिक मानदंडों और प्रवृत्तियों में हुए बदलावों आदि के बारे में सीधे प्रश्न पूछने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति होगा।	सुनिश्चित करें कि इस अनुभाग में प्रतिभागी पॉज़िटिव और निगेटिव, दोनों तरह के असर बता रहा हो।

प्रश्न	उद्देश्य	इंटरव्यूअर के लिए नोट्स
8. क्या आपके संस्था को समुदाय में हिंसा से जुड़े कोई बदलाव दिखे या नई समस्याएं दिखीं? पुरुषों के विरुद्ध हिंसा, या पुरुषों द्वारा हिंसा? क्या आप कोई पैटर्न बता सकते हैं? • क्या युवा पुरुषों और लड़कों के साथ आपकी संलग्नता में हिंसा एक समस्या के रूप में उभरी? • क्या इससे उनके खुद को देखने के तरीके और उनकी मर्दानगी की समझ पर असर पड़ा है? • आप जिन समुदायों के साथ काम करते हैं, क्या उनमें लॉकडाउन में जीबीवी (लिंग-आधारित हिंसा) बढ़ गई थी? • क्या समुदाय में जीबीवी (लिंग-आधारित हिंसा) के बारे में युवा पुरुषों व लड़कों के साथ आपकी संलग्नता के दौरान बातचीत हुई थी या फिर आपने किसी अन्य स्रोत से इसके बारे में सुना था?	यह मापने के लिए कि क्या युवा पुरुषों और लड़कों के विरुद्ध हिंसा, और युवा पुरुषों व लड़कों द्वारा की गई हिंसा से, उनके खुद को देखने के तरीके और उनकी मर्दानगी की समझ पर कोई असर हुआ है।	
9. क्या इस वैश्विक-महामारी ने युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन में कोई अन्य उभरती हुई चिंता/समस्या/बेचैनी को जन्म दिया है? • क्या इससे आपके काम पर उनकी प्रतिक्रिया/लगन पर असर पड़ा है?	जिनसे प्रतिभागी की बातचीत हुई हो उन युवा पुरुषों और लड़कों के जीवन के तमाम पहलुओं पर कोविड-19 (COVID-19) संकट और लॉकडाउन द्वारा पड़े असर को दस्तावेज़ी रूप देने के लिए।	
10. क्या इन कुछ महीनों में आपके संस्था ने और कुछ ऐसा देखा या अनुभव किया जिसे आप हमें बताना चाहते हों?	प्रतिभागी को विषय से संबंधित कोई भी अन्य किस्सा, अनुभव, चुनौती या ऐसी चीज़ें जो उसने नोट की हों, उन्हें हमें बताने का मौका देते हुए बातचीत खत्म करने के लिए।	**संकेत**: नई सीख, इस समय जारी चुनौतियों आदि से संबंधित ऐसी कोई भी चीज़ जो वे हमें बताना चाहते हों।

V. संस्थाओं का विवरण

संस्था	विवरण	लड़कों और पुरुषों के साथ काम करने के स्थान	कार्यक्रमों में जुड़े प्रतिभागियों की उम्र
एशीयन ब्रिज इंडिया	जेंडर और मर्दानगी	बनारस	15-25
जीपीएस आज़मगढ़ (EK SAATH)	जेंडर और मर्दानगी	आज़मगढ़	15-25
सहयोग इंडिया (EK SAATH)	जेंडर और मर्दानगी	हमीरपुर	कई उम्र के लड़कों के साथ
अवध पीपल्स फोरम (EK SAATH)	जेंडर और मर्दानगी	अयोध्या	15-30
तरुण चेतना समिति (EK SAATH)	जेंडर और मर्दानगी	प्रतापगढ़	15-25
वेव फाउंडेशन	जेंडर और मर्दानगी	उत्तर प्रदेश में कई जगहें	कई उम्र के लड़कों के साथ
प्रोजेक्ट खेल	जेंडर और मर्दानगी	लखनऊ	14-23
ब्रेकथ्रू	जेंडर और मर्दानगी	उत्तर प्रदेश में कई जगहें	
अस्तित्व सामाजिक संस्था	जेंडर और मर्दानगी	मुज़फ़्फ़रनगर	
ग्राम्य संस्था	पोषण	बनारस	15-25
बदलाव	रोज़गार	लखनऊ	कई उम्र के लड़कों के साथ
एच.सी.एल फाउंडेशन	रोज़गार, विकलांगता, पलायन	नॉएडा, लखनऊ	14-18
मजदूर खदान यूनियन	रोज़गार	मिर्ज़ापुर	
विज्ञान फाउंडेशन	रोज़गार, शिक्षा	उत्तर प्रदेश में कई जगहें	कई उम्र के लड़कों के साथ
पी.एस.आई.	स्वास्थ, एस.आर.एच	उत्तर प्रदेश में कई जगहें	
दिशा फाउंडेशन	शिक्षा, हिंसा	जौनपुर	कई उम्र के लड़कों के साथ
आँचल	पानी, जेंडर	सहारनपुर	14-18

THE YP FOUNDATION

द वाईपी फाउंडेशन (TYPF) एक युवा विकास संस्था है जो स्वास्थ्य समानता, जेंडर न्याय, यौनिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर युवा लोगों के नारीवादी और अधिकार-आधारित नेतृत्व को बनाता और बढ़ाता है। TYPF सुनिश्चित करता है कि युवाओं के पास उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों और नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को सूचित करने और नेतृत्व करने के लिए जानकारी, क्षमता और अवसर हों, और उन्हें सामाजिक परिवर्तन के कुशल और जागरूक नेताओं के रूप में पहचाना जाए।

MARDON WALI BAAT PROGRAMME

मर्दों वाली बात कार्यक्रम पुरुषों और लड़कों के साथ काम करता है ताकि जेंडर से जुड़े पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए मर्दानगी पर गहराई से सोच बनाई जा सकें। अनुसंधान और हस्तक्षेप डिजाइनों के माध्यम से, कार्यक्रम युवा पुरुषों और लड़कों के लिए उनके विशेषाधिकारों और कमजोरियों की पारस्परिक प्रकृति पर संवाद करने के लिए इंटरैक्टिव जगह बनाना चाहता है।

www.theypfoundation.org

@theypfoundation
The YP Foundation
@theypfoundation
The YP Foundation
TYPF Talks by The YP Foundation

CREDITS

लेख : अवली खरे, सिद्धांत पसरीचा
डाटा संग्रह : अवली खरे, सिद्धांत पसरीचा
संपादन और समीक्षा : मानक मटियानी, सागर सचदेवा
रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड : क्रिस्टीना फ़र्टाडो, विकास चौधरी
रिपोर्ट डिज़ाइन : कोकिला भट्टाचार्या

द वाईपी फाउंडेशन का प्रकाशन, अमेरिकन ज्यूइश वर्ल्ड सर्विस के सहयोग से।